सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) में निर्देशित}

मैनुअल – दस	**प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथा उपबन्धित हो।**
मैनुअल – ग्यारह	**सभी योजनओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।**

मैनुअल – बारह	**सहायिकी कार्यक्रमों के निश्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि का ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।**
मैनुअल – तेरह	**अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विषिश्टियॉ।**

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा – 4(1)(ख) के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी को संगठन/विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं जो धारा 4(1)(ख) की उपधारा (ii) से (xvii) में उल्लिखित हैं, को प्रकाशित करना बाध्यकारी है, ताकि संगठन से सम्बन्धित सूचनाएं जनता के लिए सहज रूप से पहुँच योग्य हों। अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शहरी विकास निदेशालय द्वारा 17 मैनुअल निम्नवत् प्रकाशित किये गये हैः

मैनुअल – एक, दो, तीन और चार
मैनुअल – पांच (चार खण्ड़ों में)
मैनुअल – छः, सात, आठ और नौ
मैनुअल – दस, ग्यारह, बारह और तेरह
मैनुअल – चौदह, पन्द्रह, सोलह और सत्रह

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड का गठन माह अगस्त 2001 में हुआ है। वर्तमान में शहरी विकास निदेशालय में विभिन्न संवर्गो में 43 पद सृजित/आवंटित है, जिसके सापेक्ष में मात्र 19 अधिकारी/कर्मचारी निदेशालय में तैनात है। इसके बावजूद शहरी विकास

निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारियों ने अभिलेख और सूचनाओं के रख–रखाव में कठिन परिश्रम किया है जिसका समावेश 17 मैनुअल में किया गया है।

शहरी विकास निदेशालय के मैनुअल वर्ष 2006 तैयार करने में मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड और सूचना आयोग उत्तराखण्ड के अधिकारियों का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जिसके परिणाम स्वरूप मैनुअल का प्रकाशन सम्भव हो पाया था।

मैनुअल संख्या पांच जिसमें शहरी विकास से सम्बन्धित अधिनियम, अधिसूचनाएं व शासनादेश प्रकाशित हैं, को मई 2011 तक अद्यतन करते हुए मैनुअल संख्या पांच की एक–एक प्रति राज्य सूचना आयोग के आदेशानुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय भेजी जा रही है ताकि जनता को वांछित सूचना स्थानीय निकाय में ही उपलब्ध हो सके।

शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअल तैयार करने में निदेशालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने विशेष प्रयास व परिश्रम किया है। इसके लिए निदेशालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअल मा0 आयोग द्वारा वर्ष 2006 में अनुमोदित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा – 4 की उपधारा (2) में यह निर्देश है कि प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अक्सर, स्वप्रेरणा से, जनता का नियमित अंतरालो पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़ा। अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शहरी विकास निदेशालय द्वारा इन प्रकाशनों को नियमानुसार नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहेगा। समस्त स्थानीय निकायों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने–अपने मैनुअल नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे। शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअलों को मई 2011 तक की सूचनाओं सहित द्वितीय संस्करण के रूप में अद्यतन किया जा रहा है।

(निधि मणि त्रिपाठी)

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड,

देहरादन

शहरी विकास विभाग

उत्तराखंड शासन

ऑउटकम बजट

वित्तीय (वर्ष 2011–12)

शहरी विकास विभाग

उत्तराखंड शासन

दिग्दर्शक एवं ऑउटकम बजट

वित्तीय (वर्ष 2011–12)

शहरी विकास विभाग

विभागीय दिग्दर्शक बजट

उत्तराखण्ड में शहरी विकास विभाग में नियंत्रणधीन एक नगर निगम, 32 नगर पालिका परिषदें एवं 30 नगर पंचायतें कुल 63 स्थानीय निकाय कार्यरत है। स्थानीय निकायों के अन्तर्गत राज्य में स्थित निकायों में जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार रु0 18.42 लाख है। स्थानीय निकायों के मुख्य रुप से अपने सीमान्तर्गत रहने वाले नागरिकों को 74वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुरुप संविधान के 12वीं अनुसूची के अन्तर्गत दिये गये कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुविधायें उपलब्ध कराना है। जिसमें मुख्यतः सफाई व्यवस्था, पथप्रकाश, पार्किग व्यवस्था, सीमा के

अन्तर्गत सड़कों नालियों का निर्माण आदि है। 74वें संशोधन के अनुरुप वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में जनता द्वारा चुने गये स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधि कार्यरत है।

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत शहरी विकास निदेशालय का संरचनात्मक ढॉचा निम्न प्रकार है :–

शहरी विकास निदेशालय,उत्तरांखण्ड में पुर्नगठन शासनादेश संख्या–211/iv/(1)/2010–176(सा0)/2006 दिनांक 15–4–2010 ए शासनादेश संख्या–640(1)/iv(1)/2010–176(सा)/2006 दिनांक 14–9–2010 द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति के सृजित पदों एवं उसके सापेक्ष कार्यरत/रिक्तियों का विवरण (25–2–11की स्थिति)

क्रम सं	संवर्ग/पद म	वेतनबैण्ड/ग्रे ड वेतन		कार्यरत कार्मिकों की संख्या	वर्तमा में रिक्त पदों की संख्या	शासनादेशानुसार पदों को भरे जाने का प्राविधान/अभ्युक्ति
	प्रशासनिक सेवा संवर्ग					
1	निदेशक(I A.S.)	संवर्गानुसार		**1**	**0**	
2	अपर निदेशक (P.C.S.)	संवर्गानुसार		**0**	**1**	
3	उपनिदेश	15600–39 00/6600		**2**	**0**	वर्तमान में पालिका केन्द्रियित सेवा के अधिकारीगण पदोन्नति/स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यरत है।
4	सहायक निदेशक	15600–39 00/5400		**1**	**1**	शासन द्वारा पालिका केन्द्रियित सेवा के अधिशास अधिकारी को सहायक निदेशक के पद के सापेक्ष तैनात किया गया है।
	तकनीकी सेल					

5	समन्वयक अभियंत्रण)	अधिकतम अधिशासी अभियन्ता स्त		0	1	संविदा पर आउटसोर्सिंग अथवा प्रतिनियुक्ति पर
6	अवरअभिय ता (तकनीकी)	9300–3480 0/4200		0	1	संविदा पर आउटसोर्सिंग अथवा प्रतिनियुक्ति पर
7	सहायक निरीक्षक	5200–20200/2800		0	0	मृत संवर्ग। इस पद को मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया है जबकि उ0प्र से इस पद पर आवंटित कार्मिक स्थगन पर है। कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।
	लेखा संगठन					
8	लेखाधिका ी	संवर्गानुसार		1	0	वित्त एवं लेखा संवर्ग क पद।
9	लेखाकार	9300–3480 0/4200		1	0	सहायक लेखाकार पद र पदोन्नति।
10	सहायक लेखाकार	5200–2020 0/2800		2	2	**सीधी भर्ती द्वारा। चयन हेतु अधियाचन पत्र दिनांक 30–9–2010 को प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूडकी को प्रेषित कर दिया गया है।**
	सांख्यिकी सेल					
11	अर्थ ए संख्याधिका ी	नियोजन विभाग के संवर्गोनुसार		0	1	नियोजन विभाग द्वारा नियुक्ति किया जायेगा। निदेशालय के पत्र सं,–771/विविध–93/20 0 दिनांक 9–9–2010 द्वार नियोजन विभाग से तैनाती/नियुक्ति का अनुरोध किया गया है।

12	सांख्यिकी सहायक	9300–3480 0/4200		**0**	**1**	नियोजन विभाग द्वारा नियुक्ति किया जायेगा। निदेशालय के पत्र सं,–771/विविध–93/200 दिनांक 9–9–2010 द्वारा नियोजन विभाग से तैनाती/नियुक्ति का अनुरोध किया गया है।
	मिनिस्ट्रियल संवर्ग					
13	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–3480 0/4600		**1**	**0**	पदोन्नति द्वारा भरा गया है।
14	प्रशासनिक अधिकारी	9300–3480 0/4200		**0**	**3**	**मुख्य सहायक की पदोन्नति से** ।
15	मुख्य सहायक	5200–2020 0/2800		**0**	**3**	**प्रवर सहायक की पदोन्नति से**। 02मुख्य सहायकों द्वारा उ0प्र0 से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और स्थगन पर उ0प्र0 में ही कार्यरत है। **पदोन्नति के रिक्त पदों को नियमानुसार भरा जाना विचाराधीन है।**
16	प्रवर सहायक	5200–2020 0/2400		**4**	**1**	**कनिष्ठ सहायक की पदोन्नति से।** 01 प्रवर सहायक द्वारा उ0प्र0 से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और स्थगन पर उ0प्र0 में ही कार्यरत है।
17	कनिष्ठ सहायक	5200–2020 0/1900		**4**	**1**	सीध भर्ती। 01कनिष्ठ सहायक द्वारा उ0प्र0 से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और स्थगन पर उ0प्र0 में ही कार्यरत है।
18	आशुलिपिक स डाटा एन्ट्र	5200–2020 0/2400		**0**	**3**	संविदा पर आउटसोर्सिंग

	आपरेटर					
19	वाहन चालक।	5200—2020 0/1900		**2**	**0**	कार्यरत कार्मिकों की सेव निवृत्ती या अन्यथा रिक्त होने पर मृत संवर्ग। तदोपरान्त संविदा पर आउटसोर्सिग।
20	चपरासी/ अनुसेवक	4400—7440 /1300		**5**	**0**	कार्यरत कार्मिकों की सेव निवृत्ती या अन्यथा रिक्त होने पर मृत संवर्ग, तदोपरान्त संविदा पर आउटसोर्सिग। उ0प्र0 से आवंटित 02 कार्मिक उ0प्र में ही स्थगन पर कार्यरत है/कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। **सृजित/रिक्त 03 पदों के विरूद्व प्रान्तीय रक्षक दल के कार्मिक तैनात किये गये है।**
	योगः			**24**	**19**	

नोटः—1— मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग—2 उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1260/**XXX**(2)/2010 दिनांक 07—09—2010 में दिये गये आदेशों के अनुपालन में निदेशालय में उपरोक्तानुसार सृजित 02 पद सहायक लेखाकार का अधियाचन निदेशालय के पत्रांक 1113/श0वि0नि0—विविध—92/अधियाचन/2010 दिनांक 30—09—2010 द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूडकी को पेषित किया जा चुका है।

2— वर्तमान के संरचनात्मक ढांचे में सृजित आशुलिपिक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 03 पदों को संविदा/आउटसोर्सिग से माध्यम से भरे जाने का प्राविधान है। उक्त के दृष्टिगत निदेशालय के पत्रांक 772 दिनांक 12—8—2010 द्वारा शासन से उक्त पदों को उपनगल के माध्यम से भरे जाने की प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है,जो अभी तक प्रतिक्षित है। इसके अतिरिक्त निदेशालय के संचनात्मक ढाचे के अनुसार सृजित अर्थ एवं सख्याधिकारी के 01 पद तथा सांख्यिकी सहायक के 01 पद प नियोजन विभाग से यथाशीघ्र नियुक्ति/तैनाती करने का अनुरोध किया गया है। नियोजन विभाग के स्तर से नियुक्ति/तैनाती प्रतिक्षित है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनायें

1– यूआईजी

(Urban Infrastructure and Governance)

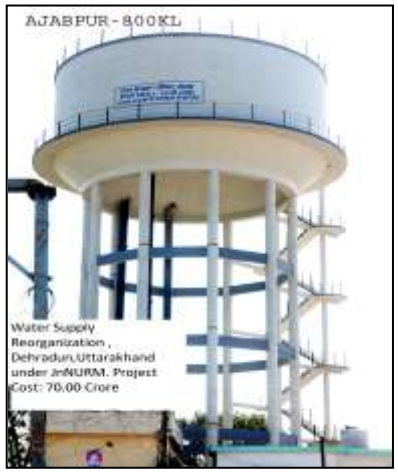

●भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल के लिए मिशन अवधि 2005–12 में कुल रू0 205.34 करोड़ की राशि क्रेन्द्राश के रूप में प्राविधानित की गयी थी। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त प्राविधानित धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात् रू0 20.5 करोड़ क्षमता विकास एवं O&M हेतु आरक्षित कर ली गयी है तथा यह धनराशि केन्द्र सरकार स्तर से व्यय की जायेगी। अतः फलस्वरूप राज्य को यू0आई0जी0 के अन्तर्गत केन्द्रांश का आवंटन रू0 184.84 करोड़ ही रह गया है।

●

क्त आवंटन के सापेक्ष भारत सरकार से कुल लागत रू0 233.73 करोड़ की 08 परियोजनायें स्वीकृत करायी जा चुकी है। जिनमें केन्द्रांश रू0 183.86 करोड़ सम्मिलित है। इस प्रकार केन्द्र द्वारा राज्य के लिये प्राविधानित राशि का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

स्वीकृत

- योजनाओं का विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि करोड़ रूपये में)

	स्वीकृत परियोजना/वर्ष	स्वीकृत परियोजना लागत			अवमुक्त धनराशि	परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि	परियोजना समाप्त होने की तिथि	व्यय	
			राज श (योज लाग का 2 प्रतिश)						

	जलापूर्ति, देहरादून/ 2007-08		14 0		**52.5**	दिसम्ब 200	मई, 201	41.3	
	जलापूर्ति, हरिद्वार/ 2007-08		9.		**44.4**	दिसम्ब 200	मई, 201	46.2	
	जलापूर्ति, नैनीताल/ 2007-08		1.		**2.74**	दिसम्ब 200	अगस्त, 201	2.7	
	सॉलिड वे मैनेजमेंट, देहरादून/ 2008-09		4.		6.15	मई, 2008	दिसम्बर, 2009	0.37	

	सॉलिड वे मैनेजमेंट, हरिद्वार / 2008-09		3.		4.18	दिसम्बर, 2008	मार्च, 2010	0.00	
	देहरादून चौराहों सुधार / 2008-09		5.		7.36	जनवरी, 2009	मार्च, 2011	7.36	
	हरिद्वार चौराहों सुधार / 2008-09		3.		5.01	दिसम्बर, 2008	जुलाई, 201	4.01	
	सीवरेज सिस्टम, नैनीताल / 2008-09		3.		4.91	फरवरी, 2009	जनवरी, 2012	4.90	
	योग		**49**		**118.7**			**106.94**	

नोटः– उल्लेखनीय है

यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्राविधानित धनराशि रू0 184.84 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है फिर भी देहरादून शहर की आवागमन समस्या के दृष्टिगत् देहरादून नगर में 3 Under pass/subway की रू0 10.28 करोड लागत की डी0पी0आर0 भारत सरकार को प्रस्तुत है। जिसका अप्राईजल हो चुका है तथा भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।

स्टूम्लेस पैकेज

●मिशन टाउन देहरादून के लिये 100 करोड़ तथा हरिद्वार एवं नैनीताल के लिये क्रमशः 50–50 करोड़ की राशि केन्द्रांश के रूप में प्राविधानित की गयी थी। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त प्राविधानित धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात् रू0 20.00 करोड़ क्षमता विकास एवं O&M हेतु आरक्षित कर ली गयी है तथा यह धनराशि केन्द्र सरकार स्तर से व्यय की जायेगी। अतः फलस्वरूप राज्य को स्टूम्लेस पैकेज के अन्तर्गत केन्द्रांश का आवंटन रू0 180.00 करोड़ ही रह गया है।

● उक्त आवंटन के सापेक्ष भारत सरकार से कुल लागत रू0 165.79 करोड़ की 04 परियोजनायें स्वीकृत करायी जा चुकी है। जिनमें केन्द्रांश रू0 132.63 करोड़ सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को रू0 44.34 करोड़ केन्द्रांश की 02 परियोजनायें प्रेषित की जा चुकी है जिन पर स्वीकृति अपेक्षित है।

● स्वीकृत योजना का विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि करोड़ रूपये में)

	स्वीकृत परियोजना/	स्वीकृत परियोजना लागत	अवमुक्त	परि			

	वर्ष	केन्द्रांश (योजना लागत क 80 प्रतिश	राज्यां (योजन लागत का 20 प्रतिशत	कुल परियोज ा लाग	धनराशि	योजन ा प्रारम्भ होने की तिथि				
	सीवरेज सिस्ट देहरादून/ 2008 09	43.7	10.	54.	13.6	फर री, 200			➢ न्ति कि तथ का ➢ S	

	सीवरेज सिस्ट देहरादून फेस–2 2009-10	50.2	12.	62.	14.4	फर री, 201			➢ ST ➢ ीवर कि
	सॉलिड वेस्ट मैनेजमे नैनीताल / 2010–11	7.4	1.	9.	2.3	ुन 201			➢ ार0 गर प्राप
	योग	**93.9**	**23.**	**11 4**	**28.1**				

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में अपरिहार्य कारणो से निरस्त की गयी स्वीकृत परियोजना का विवरण

(धनराशि करोड़ रूपये में)

	स्वीकृत परियोजना / व	स्वीकृत परियोजना लागत			अव क्त धनरा की तिथि	अव क्त	व्यय	
		केन्द्र श (योज लाग का 8 प्रतिश	राज्य श (योज लाग का 2 प्रतिश	कुल परियोज लागत				
	चैनेलाईजेशन आफ स्व हरिद्वार / 2010–11	31	7.	39.				➢ परियो

परियोजनायें जो भारत सरकार में प्रस्तुत की गयी तथा जिनका अप्रेजल हो चुका है/अप्रेजल किया जा रहा है

परियोजनाये जिनका अप्रेजल हो चुका हैः–

(a) हरिद्वार में सीवरेज (लाल मन्दिर एवं कनखल एरिया) की दो डी0पी0आर0 रू0 26.98 करोड़ का अप्रेजल भारत सरकार की एजेन्सी द्वारा कराया जा चुका है। प्रश्नगत् डी0पी0आर0 की कुल लागत रू0 26.98 करोड़ में रू0 21.58 केन्द्रांश राशि सम्मिलित है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है।

परियोजना जिसका अप्रेजल अन्तिम चरण मे हैः–

(a) नैनीताल में सड़क के चौड़ीकरण/पार्किग की रू0 30.96 करोड लागत की दो डी0पी0आर0 भारत सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है जिनका अप्राईजल किया जा रहा है। प्रश्नगत् डी0पी0आर0 की कुल लागत रू0 31.00 करोड़ में रू0 24.76 केन्द्रांश राशि सम्मिलित है।

भारत सरकार में स्वीकृति हेतु लम्बित 02 डी0पी0आर0 मे केन्द्रांश की कुल धनराशि 46.32 करोड़ है तथा देहरादून व हरिद्वार नगर के लिये स्वीकृत परियोजनाओ की केन्द्रांश राशि रू0 125.18 करोड़ है। इस प्रकार स्टूम्लस पैकेज के अन्तर्गत कुल उपलब्ध केन्द्रांश धनराशि रू0 180.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 178.96 करोड की परियोजनाये भारत सरकार को प्रेषित करते हुये लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।

सिटी बस सर्विस के लिये पैकेज

- मिशन शहरों देहरादून हेतु 60, हरिद्वार हेतु 60 तथा नैनीताल हेतु 25 बसों के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा 27.18 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 13.59 करोड़ कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड परिवहन निगम को अवमुक्त किया जा चुका है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा सभी 145 बसों को प्राप्त कर लिया गया है एवं जिसका संचालन प्रारम्भ हो गया है। 145 बसो की कुल लागत मूल्य रू0 19.10 करोड़ के सापेक्ष रू0 13.55 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

धनराशि

करोड़ रूपये में

		स्वीकृत परियोजना / वर्ष	स्वीकृत परियोजना लागत							टिप्पणी
			केन्द्रांश (योजना लागत का 80 प्रतिशत)	राज्यांश (योजना लागत का 20 प्रतिशत)	[illegible]		[illegible]			
		सिटी बस सर्विस, 2008-09	9.1	2.2						➢ 45 बसे प्राप्त हो गयी जिनका संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा है।
		सिटी बस सर्विस, 2008-0	2.3	0.5						
		सिटी बस,सर्वि 2008-0	10.3	2.5						

			21.7	5.4					

2–

यूआईडीएसएस

एमटी (**Urban Infrastructure Scheme for Small and Medium Towns**)

- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत नॉन मिशन शहरों के लिए मिशन अवधि 2005–12 में कुल रू0 46.07 करोड़ की राशि क्रेन्द्राश के रूप में प्राविधानित की गयी थी।
- उक्त आवंटन के सापेक्ष भारत सरकार से कुल लागत रू0 61.73 करोड़ की 01 परियोजना स्वीकृत करायी जा चुकी है। जिनमें केन्द्रांश रू0 49.39 करोड़ सम्मिलित है। इस प्रकार केन्द्र द्वारा राज्य के लिये प्राविधानित राशि का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

(धनराशि करोड़ रूपये में)

	स्वीकृत परियोजना/वर्ष	स्वीकृत परियोजना लागत					प योजना समाप्त होने की तिथि		टिप्पणी
		केन्द्रांश (योजना लागत का 8 प्रतिशत)	राज्यांश (योजना लागत का 20 प्रतिशत)						

	सीव ज सिस्ट , मसूरी / 2008 09	49 39	12. 4				म र्च, 20		➢ कि0मी0 पाईप बिछा का कार्य पूर्ण एवं 2 कि0मी0 पाईप लाई बिछाने का कार्य प्रगा पर। ➢ TP के लिये टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम चरण।
	यो	**49 3**	**12.**						

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनायें

बीएसयूपी (**Basic Services to the Urban Poor**)

- योजनान्तर्गत चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल के लिए मिशन अवधि 2005–12 में भारत सरकार द्वारा कुल रू0 97.84 करोड़ का केन्द्रांश स्वीकृत है।
- पूर्व मे भारत सरकार द्वारा कुल केन्द्रांश रू0 27.97 करोड की परियोजनाये स्वीकृत थी।

- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2010 की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार अवशेष केन्द्रांश रू0 65.27 करोड़ के सापेक्ष एक विशेष अभियान चलाते हुये कुल रू0 49.89 करोड़ की धनराशि की डी0पी0आर0 भारत सरकार को माह फरवरी, 2010 में प्रेषित की गयी जिनमें केन्द्रांश धनराशि रू0 37.30 करोड़ है।

- कुल केन्द्रांश रू0 97.84 करोड़ के सापेक्ष अब तक कुल केन्द्रांश रू0 65.27 करोड़ की परियोजनाये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है मिशन शहरो देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार द्वारा डी0पी0आर0 उपलब्ध न कराये जाने पर, अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 32.57 करोड़ को भारत सरकार से विशेष अनुरोध करते हुये आई0एच0एस0डी0पी0 परियोजनाओ हेतु उक्त केन्द्रांश को स्थानान्तरित कराया गया।

इस प्रकार कुल उपलब्ध केन्द्रांश धनराशि रू0 65.27 करोड़ के सापेक्ष रू0 65.27 करोड की परियोजनाये भारत सरकार से स्वीकृत कराते हुये शत्–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।

पूर्व मे स्वीकृत परियोजनाओ का विवरण

(धनराशि करोड़ रूपये में)

	स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत परियोजन लागत		अवमु त किश			टिप्पणी

	राम मन्दि कुष्ठ आश्र देहरादून									➢ 4 मकान का कार्य पूर्ण तथा अन्य 13 मकानों में लिंट स्तर तक कार्य पूर्ण।

	शांति कु रोग आश्र देहरादून									➢ 8 मकानों में कार्य पूर्ण तथा सीवरेज एवं सैप्टिक टैं का कार्य पूर्ण। ➢ ।मुदायिक भवन में प्लास्टर का कार्य प्रगति पर।
	रोटरी कु रोग आश्र देहरादून									➢ 4 मे से 22 मकानो में छत तक कार्य पूर्ण तथा सैप्टि टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है।
	चकशाह नगर, देहरादू									➢ 3 फरवरी, 2010 को कार्यादेश जारी। ➢ गर निगम को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देष।
	पाण्डेवाला, हरिद्वार									➢ 6 ब्लॉक जिनमें प्रत्येक ब्लॉक में 16 आवास बनने है (ब्लॉक मे तृतीय तल की छत डाली जा चुकी है। (ब्लॉक में द्वितीय तल की छत डाली जा चुकी है। (ब्लॉक में प्लिन्थ स्तर तक कार्य पूर्ण, 03 ब्लॉक चिनाई का कार्य प्रगति पर हैं एवं नाला निर्माण का प्रगति पर है।

	दुर्गापुर, नैनीताल									➢ र्यदायी संस्था पी0डब्लू0डी0 द्वारा बाउन्ड्री वॉल निर्मा कार्य आरम्भ।
योग										

		स्वीकृत परियोजना लागत		अवमुक्त किश्त			टिप्पणी

										कार्योदेश दिनांक 18 जनवरी, 2009 करे दिया गया थ किन्तु स्थलीय विवाद के कारण कार्य विलम्बित हुअ विवाद सुलझाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा उन दरों प कार्य में असमर्थता व्यक्त की गयी जिस कारण पु निविदायें आमंत्रित की गयी। पुनः आमंत्रित न्युनतम निवि 24.20 प्रतिशत अधिक होने पर निविदा का वर्तमान दरों प आंकलन कराया जा रहा है।

										परियोजना में भूमि विवाद होने के कारण दो वर्ष बाद काफी प्रयासो के उपरान्त भी प्रारम्भ नही हो पा रहे है उक्त परियोजनाओ को निरस्त करने हेतु शासन को प प्रेषित किया गया है।
	योग									

वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओ का विवरण निम्नवत् हैं:–

(धनराशि करोड़ रूपये में)

	स्वीकृत	स्वीकृत परियोजना लागत	नि	अवमुक्त किश्त		परियोजना	टिप्पण

	परियोजन			कुल परियो ना लाग	मंत होन वाल भवन की संख		धनराशि		समाप्त होने की तिथि	
	रामनग मलिन बस्ती, देहरादून			11 59	2 4		2.9		सितम्बर, 2011	रामनगर मलिन बस्ती में अ अवस्थापना विकास कार्य एवं 1159.88 लाख की योजना स्व लाख अवमुक्त। प्रथम बार दिनां केवल दो निविदायें प्राप्त होने आमंत्रित की गयी। पुनः दो न्यूनतम निविदा आगणन से 1. पर स्वीकृति हेतु शासन को संद
	निरंजन पुर, ब्रह्मपुरी, फेज–1, देहरादून			1 1	2 0		2.79		सितम्बर, 2011	निविदा स्वीकृत धनराशि से स्वीकृति हेतु शासन को संदर्भित
	निरंजन पुर, ब्रह्मपुरी, फेज–2, देहरादून			16 67	4 1		4.17		नवम्बर, 2011	निविदाये आमंत्रण की कार्यवाही
	नारायण नगर, नैनीताल			10 49	1 1		2.62		सितम्बर, 2011	वन विभाग से भूमि स्थानान्त परीक्षण कराया जा रहा है।

योग				4 8	0		12.4			

आईएचएसडीपी (**Integrated Housing and Slum Development Program**)

- योजनान्तर्गत मिशन अवधि 2005–12 में कुल रू. 63.58 करोड का केन्द्राश भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है ।
- बी.एस.यू.पी. में उपलब्ध धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण केन्द्रांश की अवशेष रू. 32.57 करोड धनराशि को आई.एच.एस.डी.पी. में पुनर्विनियोजित किया गया। अतः योजनान्तर्गत अब कुल रू. 96.15 करोड का केन्द्रांश उपलब्ध है।
- प ूर्व मे भारत सरकार द्वारा कुल केन्द्रांश रू0 2.91 करोड की परियोजनाये स्वीकृत थी।
- ुल 90.57 करोड़ केन्द्रांश धनराशि की परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत।
- ाननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2010 की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार अवशेष केन्द्रांश रू0 60.57 करोड़ के सापेक्ष एक विशेष अभियान चलाते हुये कुल रू0 155.40 करोड़ की धनराशि की डी0पी0आर0 भारत सरकार को माह फरवरी, 2010 में प्रेषित की गयी जिनमें केन्द्रांश धनराशि रू0 87.66 करोड़ है। बी0एस0यू0पी0 योजना से कुल रू0 32.57 करोड़ केन्द्रांश धनराशि आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत स्थानान्तरित की गयी इस प्रकार योजनान्तर्गत कुल रू0 96.15 करोड़ केन्द्रांश धनराशि उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष कुल रू0 90.57 करोड़ केन्द्रांश धनराशि की परियोजनाये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गयी हैं। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त शेष धनराशि रू0 5.64 करोड़ क्षमता विकास एवं O&M हेतु आरक्षित कर ली गयी है तथा यह धनराशि केन्द्र सरकार स्तर से व्यय की जायेगी।

COMMUNITY CENTRE AT KEWAT MOHALLA
UNDER IHSDP SCHEME AT
SRINAGAR GARHWAL

इस प्रकार कुल उपलब्ध केन्द्रांश धनराशि रू0 90.57 करोड़ के सापेक्ष रू0 90.57 करोड की परियोजनाये भारत सरकार से स्वीकृत कराते हुये शत्–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।

पूर्व मे स्वीकृत परियोजनाओ का विवरण

(धनराशि करोड़ रूपये में)

		स्वीकृत परियोजना लाग			निर्मित होने वाले भवनों की संख्य	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त			परियोजना समाप्त होने की तिथि
				कु परि जन लाग			धनराशि		
				3	5		0.66		अगस्त, 201
				5	17		2.20		मार्च, 2010

	योग			5 8	23		2.8			

भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओ की माह मार्च, 2010 में सचिव, आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित सी0एस0एम0सी0 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। जिनका विवरण निम्नवत् है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(धनराशि करोड़ रूपये में)

	स्वीकृ परियोज	स्वीकृत परियोजना लागत				अवमुक्त प्रथम किश्त			परि जन समाप होने तिथि	टिप्पणी
				कुल परियोजन लागत		व				
	महुआ ाबरा			9.25		म र्च 201 0			अग स्त, 201	72 मका निमार्णाधीन 30 पूर्ण।
	महुआ ड़ागंज			11.8		म र्च 201 0			अग स्त, 201	187 मकान निमार्णाधीन 20 पूर्ण।
	दिनेश र			11.7		म र्च			अग स्त,	153 मका निमार्णाधीन 15 पूर्ण।

						20 0			201	
	काशीप र			11.9		म र्च 20 0			अग स्त, 201	223 मका निमार्णाधीन
	लालकु आ			3.59		म र्च 20 0			अग स्त, 201	फाउन्डेशन का प्रारम्भ
	पिथौर गढ़			10.9		म र्च 20 0			अग स्त, 201	126 मका निमार्णाधीन 12 पूर्ण।
	कालाढ़ गी			10.4		ज न 20 0			अग स्त, 201	169 मका निमार्णाधीन 12 पूर्ण।
	किच्छा			5.63		अ गस , 20 0			अग स्त, 201	65 मका निमार्णाधीन 9 पूर्ण।
	चम्पाव			3.81		अ गस , 20 0			अग स्त, 201	फाउण्डेशन का प्रारम्भ
	मसूरी			5.10		ज ला 20 0			अग स्त, 201	फाउण्डेशन का प्रारम्भ
	अल्मोड			8.33		ज ला 20 0			अग स्त, 201	25 मका निमार्णाधीन 33 पूर्ण।
	जसपुर (फेस–1			6.30		सि तम्ब र, 20 0			अग स्त, 201	15 मकान निमार्णाधीन
	जसपुर			1.57		सि			अग	33 मकान

	(फेस–2					तम्बर, 2010			स्त, 2011	निमार्णाधीन
	लण्ढौरा (फेस–1			10.1		सितम्बर, 2010			अगस्त, 2011	12 मकान निमार्णाधीन
	लण्ढौरा (फेस–2			2.58		सितम्बर, 2010			अगस्त, 2011	82 मकान निमार्णाधीन 15 पूर्ण।
	हल्द्वानी			13.4		फरवरी 2011			अगस्त, 2011	15 मकान निमार्णाधीन
	हल्द्वानी – काठगोदाम			11.8		फरवरी 2011			अगस्त, 2011	20 मकान निमार्णाधीन
	विकास नगर			3.34		सितम्बर, 2010			अगस्त, 2011	26 मकान का कार्य निर्माणाधीन
	मंगलौर			13.4		फरवरी 2011			अगस्त, 2011	33 मकान निमार्णाधीन
	योग			**155.42**						

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 परियोजना के अन्तर्गत प्रगतिशील कार्यो के छायाचित्र

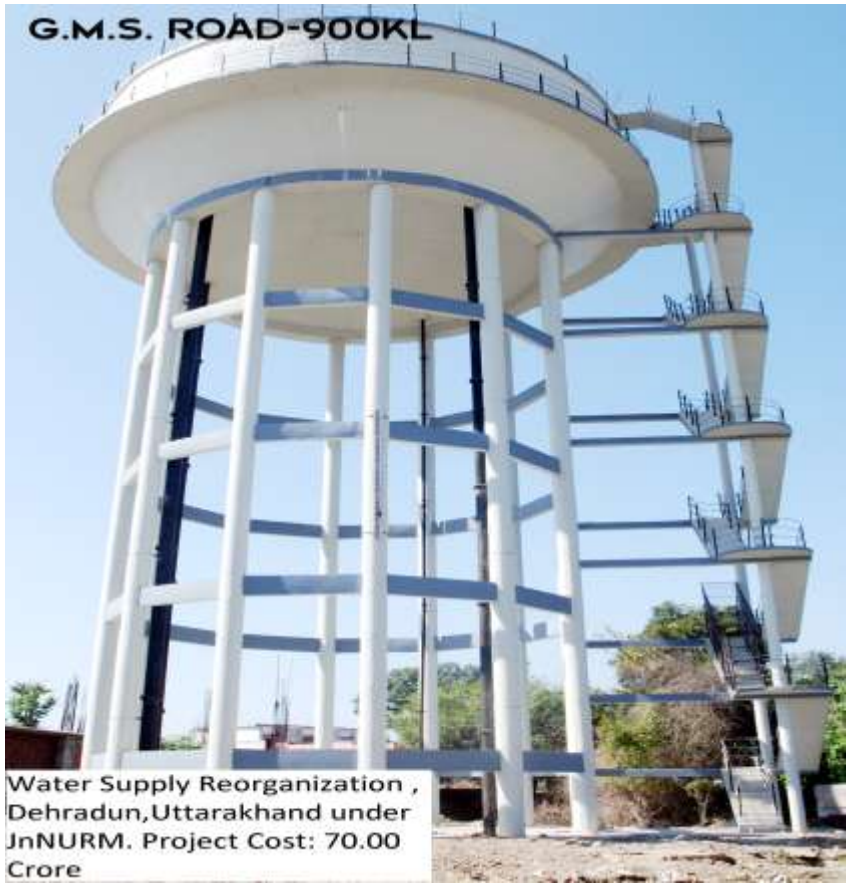

Water Supply Reorganization , Dehradun,Uttarakhand under JnNURM. Project Cost: 70.00 Crore

HARIDWAR
BHOPATWALA
OVERHEAD TANK
Water Supply Reorganization ,
Haridwar,Uttarakhand under JnNURM. Project
Cost: 47.84 Crore

HARIDWAR BHOPAT WALA
INFILTRATION WELL
Water Supply Reorganization ; Haridwar,Uttarakhand under
JnNURM. Project Cost: 47.84 Crore

Sewerage System Nainital. Project Cost Rs 19.6 Cr

Water Supply Reorganization , Nainital. Project Cost Rs 5.47 Cr.

BSUP- Shati Kusth Ashram, Dehradun. Project Cost: Rs 1.37 Cr.

BSUP- Pandey Wala, Haridwar. Project Cost: Rs 4.34 Cr.

IHSDP Photographs

Photo of Construction Activities at Pauri

Project Cost Rs: 4.52 Cr.

IHSDP Photographs

Photo of Construction Activities at Srinagar
Project Cost Rs.: 1.33 Cr.

बिन्दु संख्या :–5

शहरी विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजनागत मद में प्राविधान और स्वीकृतियों की स्थिति तथा व्यय विवरण

(अनुपूरक सहित)

(धनराशि लाख रू

क्र सं0	अनुदान सं0–13, 30 एवं 31 , लेखा शीर्षक /योजना	प्रस्तावित परिव्यय	आय–व्य क में योजनावार प्राविधान	स्वीकृ	व्यय विवरण
1	2217–03–191–01–0101–20 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (केन्द्र सहायतित)	81.9	67.7	30.3	10
2	2217–03–800–01–0102–20 कम लागत के व्यक्तिगत शौचालय (केन्द्र सहायतित)	53.1	147.6	0.0	0
3	2217–03–191–03–0302–42 मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन	485.0	43.0	0.0	0
4	2217–03–191–03–0303–20 **(UA-URIF)** **उत्तरांचल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि**	500.0	125.0	0.0	0

5	2217–03–191–03–0305–20 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	1862.0	820.7	154.6	73
6	2217–03–191–03–0308–20 संक्रमण शील क्षेत्रों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं क विकास	25.0	0.0	0.0	0
7	2217–03–191–03–0309–20 व 42 नगरीय क्षेत्रों में सार्वभौम रोजगार योजना	22.5	18.1	0.0	0
8	2217–191–97–9701–16 **(बाह्य सहायतित)** **नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान**	11724.	11506.	2669.	3003
9	2217–03–800–01–0105–20 राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (NURM) (केन्द्र सहायतित)	21402.	18772.	311.9	0
10	2217–03–191–01–0102–20 आवास एवं मलिन बस्ती सुधार (IHSDP) (केन्द्र सहायतित)	4344.0	5729.6	4393.	1350
11	2217–03–800–01–0104–42 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण UIDSSMT	1363.7	3536.2	0.0	0
12	2217–001–08–42 व 16 परियोजनाओं की प्रारंभिक तैयारियां एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु	100.0	45.4	45.4	0
13	2217–03–191–03–0306–42 कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था	0.0	0.0	0.0	0
14	2217–03–088–04–22 कंप्युटराईजेशन एण्ड जी.आई.एस.	150.0	25.0	0.0	0
15	2217–80–8..–01–0107–20 हरिद्वारा कुंभ मेला हेतु अवस्थापना विकास	0.0	1500.0	0.0	0
16	2217–03–800–01–0106–20 बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर (BSUP) (NURM व अन्तर्गत केन्द्र सहायतित)	1968.9	4461.0	1305.	90
17	2217–04–001–02 शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद	0.0	19.5	19.5	17
18	2217–80–800–03 हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान	0.0	173.3	173.3	163
19	2217–80–800–06 मेला प्राधिकरण का अधिष्ठान	0.0	13.3	13.3	0
20	2217–80–800–05 नगर पालिका परिषद, भवाली को अनुदान	0.0	50.0	50.0	25
	कुल योग	**44082.**	**47054.**	**9168.**	**4732.**

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा संचालित योजनाऐं :–

1– स्वर्ण जयंती

शहरी रोजगार योजना

केन्द्र पुरोनिधानित इस योजनान्तर्गत संषोधित दिषा–निर्देषा के अुनसार वर्ष 2010–11 में केन्द्रांष तथा राज्यांष का अनुपात 90:10 है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांष के रूप में रू0 546.34 लाख की धनराषि आवंटित की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांष रू0 546.34 लाख के सापेक्ष राज्यांष रू0 60.70 लाख की धनराषि अवमुक्त की गयी है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजनगार योजना की उपयोजना निम्नवत् है :–

1– स्वतः

रोजगार योजना :–

इसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में निवासरत बेरोजगार एवं आंषिक रूप से बेरोजगार व्यक्ति को अपना निजी व्यवसाय की व्यवस्था हेतु अधिकतम रू0 2,00,000/– तक की परियोजना लागत के सापेक्ष जिला नगरीय विकास अभिकरण/नगर निकाय द्वारा 25 प्रतिषत अनुदान (अधिकतम राषि 50,000/–) दिये जाने का प्राविधान है, जबकि 05 प्रतिषत अंषदान लाभार्थी को भी देना आवष्यक है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू0 316.80 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 792 लाभार्थी निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2011 तक रू0 208.55 लाख धनराषि व्यय कर 698 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

2– स्वतः

रोजगार प्रषिक्षण कार्यक्रम :–

इस योजना के अंतर्गत निर्धन पात्र लाभार्थियों को आवष्यकतानुसार संबंधित रोजगार में प्रषिक्षण दिलाये जाने का प्राविधान है। जिसकी व्यवस्था डूडा/नगर निकाय द्वारा आई0टी0आई0/राजकीय संस्थान सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से (मास्टर क्राफ्ट मैन की सहायता से) की जाती है। प्रषिक्षण की अवधि तीन से छः माह होती है। जिसमें कम से कम 300 घण्टे प्रषिक्षण होना अनिवार्य है।

योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत प्रषिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू0 290.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 2900 लाभार्थी निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष रू0 43.18 लाख धनराषि व्यय कर 1598 लाभार्थियों को माह फरवरी, 2011 तक प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा शेष लाभार्थियों का प्रषिक्षण का कार्य माह मार्च 2011 तक पूर्ण हो जायेगा।

3—
नगरीय

मजदूरी योजना :—

योजनान्तर्गत मलिन बस्ती वासियों को जन—मूलभूत आवष्यकतायें जैसे :— सड़क/नाली, पेयजल, सामुदायिक केन्द्र, नाला/सीवर, स्ट्रीट लाईट, सामुदायिक शौचालय आदि का कार्य कराये जाने का प्राविधान है। इन कार्यो के माध्यम से बेरोजगार निर्धन को मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाना योजना का मुख्य उद्देष्य है।

योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देष्य से मलिन बस्तियों में सड़क, नाली, खड़जा आदि का निर्माण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू0 277.97 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 74056 मानवदिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2011 तक रू0 219.97 लाख धनराषि व्यय कर 80940 मानवदिवस सृजित किये जा चुके है।

4— थ्रिफ्ट एण्ड

क्रेडिट योजना :—

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत नगरीय निर्धन महिलाओं में बचत की आदर पैदा करने के उद्देष्य से उनकी बचत—ऋण समितियों का गठन कराये जाने का प्राविधान है, जिसमें वे आम सहमति से बचत द्वारा एकत्रित धनराषि में से अपनी छोटी—छोटी आवष्यकताओं हेतु ऋण प्राप्त कर सके। इन समूहों को एक वर्ष तक क्रियाषील रहने के पष्चात् बचत की गयी धनराषि के समकक्ष (अधिकतर प्रति सदस्य एक हजार रूपये तक) मैचिंग ग्राण्ट प्रदान की जाती है। ताकि समूहों के सषक्तिकरण के साथ—साथ उन्हें रोजगार परक कार्यक्रमों से जोड़ते हुए दीर्धकाल में स्वावलम्बी बनाया जा सके। योजनान्तर्गत 10 से 25 महिलाओं तक से समूह का गठन किये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू0 43.75 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 175 समूह निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष माह फरवरी 2011 तक रू0 3.83 लाख धनराषि व्यय कर 40 समूहों का गठन किया जा चुका है।

2— कम लागत

के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना (आई0एल0सी0एस0) :—

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010—11 में कम लागत के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना आरम्भ की गयी है, जिसका उद्देष्य शुष्क शौचालयो को जल प्रवाहित शौचाल में परिवर्तित करना तथा शौचालय रहित घरों में शौचालय का निर्माण करना है।

योजनान्तर्गत केन्द्रांष 75 प्रतिषत, राज्यांष 15 प्रतिषत एवं लाभार्थी अंषदान 10 प्रतिषत निर्धारित है। सर्वेक्षण में 06 नगर निकायों क्रमषः देहरादून, मंगलौर, रूड़की, हल्द्वानी, चमोली एवं रूद्रपुर के लिए कुल 1613 यूनिट शुष्क शौचालय पाये गये। भारत सरकार द्वारा उक्त 1613 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु कुल रू0 1.63 करोड़ की डी0पी0आर0 स्वीकृत की गयी है। भारत

सरकार द्वारा केन्द्रांष के रूप में रू0 123.00 लाख अवमुक्त किया गया है और राज्यांष रू0 24.60 लाख अवमुक्त किया गया है। योजनान्तर्गत कुल 1204 यूनिट शौचालयों पर निर्माण पूर्ण हो चुका है। नगर निगम, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत 761 यूनिट शौचालय के सापेक्ष 409 यूनिट शौचालयों का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं कर लिया गया है।

Investment Program Management Unit
Uttarakhand Urban Sector Development Investment Program
Government of Uttarakhand
New ISBT Complex, Hardwar By-Pass, Majra, Dehradun
Telephone +91-135-2643894, Tele-fax +19-135-2643895
Email: uusdip@gmail.com

उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तृत विवरण (ए0डी0बी0)

Loan No-2410:IND

1–एशियन विकास बैंक (ए0डी0बी0) सहायतित परियोजनायें :–

मूलभूत बेहतर शहरी संरचना व सेवाओं की आवश्यकताओं की प्रर्ति व उचित प्रबन्धन प्रदान कर क्षेत्र की सामाजिक, अर्थिक व गरीबी कम करने की दिशा में सहयोगी है। इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक (ADB) ने नगरीय विकास की भूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड नगरीय विकास निवेश कार्यक्रम के लिए लगभग 1400 करोड की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2–कार्यक्रम के उद्देश्य :

कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

•भारत सरकार के विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के विकास कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना।

•प्रदेश की समाजिक व आर्थिक क्षेत्रीय विकास नीति के अनुसार स्थानीय विकास में सहयोग प्रदान करना

•पर्यावरण में सुधार व गरीबी उत्थान कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना

•शहरी विकास की योजनाओं का निर्धारण, कुशल प्रबंधन, गवर्नेन्स इत्यादि सम्बन्धित विषयों पर क्षमतावर्धन।

1.योजना की निर्धारित अवधि–2008–2016

2.योजना की कुल लागत–लगभग रू0 2000 करोड

3.ए0डी0बी0 ऋण की धनराशि–लगभग रू0 1400 करोड

4.राज्य सरकार का अशंदान–लगभग रू0 600 करोड

5.योजना के चरण [Tranches] –सम्पूर्ण योजना चार चरणों में विभाजित है। प्रत्येक चरण की अनुमानित लागत का विवरण निम्नवत है।

चरण सं0	अवधि	अनुमानित लागत	ए0डी0बी0 ऋण	राज्यांश
प्रथम	2008–2012	लगभग रू0 344 करोड	लगभग रू0 240 करोड	लगभग रू0 104 करोड
द्वितीय	2009–2013	लगभग रू0 312 करोड	लगभग रू0 220 करोड	लगभग रू0 92 करोड
तृतीय	2010–2014	लगभग रू0 584 करोड	लगभग रू0 408 करोड	लगभग रू0 176 करोड
चतुर्थ	2011–2016	लगभग रू0 760 करोड	लगभग रू0 532 करोड	लगभग रू0 228 करोड
योग		लगभग रू0 2000 करोड	रू0 1400 करोड	रू0 600 करोड

3– योजना में सम्मिलित नगर/स्थान तथा चरणवार कराये जाने वाले कार्य–

योजना के अन्तर्गत 31 नगरों/स्थानों का चयन किया गया है। प्रत्येक चरण [tranch] में सम्मिलित नगरों/स्थानों तथा वहां पर कराये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नांकित है –

ट्राँच – 1

कार्य		नगर/स्थान का नाम
वाटर सप्लाई	–	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल
सीवरेज	–	देहरादून

ट्राँच – 2

वाटर सप्लाई	–	देहरादून, नैनीताल, रूद्रपुर
सीवरेज	–	रूद्रपुर
मलिन बस्त सुधार	–	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रूद्रपुर

ट्राँच – 3

वाटर सप्लाई	–	रूड़की, श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाषी, गोपेष्वर, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी, काषीपुर, किच्छा, रामनगर
सीवरेज	–	रूड़की, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ चम्पावत, हल्द्वानी, काशीपुर, किच्छा, रामनगर, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट।

ट्राँच – 4

शहरी सड़क तथ		रूड़की, नई टिहरी, श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाशी, गोपेश्वर, रूद्रप्रयाग, रूद्रपुर, काशीपुर, अल्मो

.	यातायात सुधार ए	बागेष्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी
	ठोस अपषिष्ट प्रबंधन	
.	ठोस अपषिष प्रबंधन (Solid Waste Management)	हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट, जोशीमठ, रूड़की, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनथ, मसूर कोटद्वार, मंगलौर, बाजपुर, रामनगर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज।

प्रथम ट्रांच के प्रस्तावित कार्यों का विवरण तथा भौतिक स्थिति

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WSS01 D	**देहरादून स्थित कोर एरिया जलापूर्ति हेतु वितरण प्रणाली क बिछाना।** ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 16.08. 2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 15.08.	39.15	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चु लगभग 15 कि.मी. की लाईन डाल क्षेत्र में लक्ष्मी रोड पर बिछायी ज है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		2012 ● डस्ट्रीब्यूषन पाईप लाईन की लम्बाई 168 किमी0		
	WSS02D	देहरादून में बॉदल नदी श्रोत से दिलाराम बाजार स्थित जल कल तक कच्चा पानी लाने हेतु पाईप लाइन बिछाना। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 30.01.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 29.04.2011 ● ाईप लाईन की लम्बाई 14 किमी0	11.35	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया लगभग 6.5 कि.मी. की लाईन चुकी है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WSS03 D	देहरादून में मौजूदा पेयजल आपू व्यवस्था में पम्प ईकाईयों एवं वाल्व बिजली के उपकरणों को बदलना तथ पम्प हाउसों का जीर्णोधार। ● र्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.08.2010 ● र्य पूर्ण होने की तिथि 11.05.2011 ● म्पिंग प्लान्टों की संख्या 52(38 S+14H	4.81	पैकेज का अनुबन्ध गठित किय चुका है। Site investigation, shifting, office establish confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। तकनीकी डि एवं डेटा पर अनुमोदन दिया जा चु 23 मोटरों की आपूर्ति की जा चु तथा इसी माह पम्पों की आपूर्ति पू ली जायेगी।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WSS04D	देहरादून नगर में पेयजल व्यवस्था हे 15 नग स्टैटिक एवं मोबाईल जनरेटर की व्यवस्था। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 05.06.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 04.12.2011 ● 0 मोबाईल जनरेटर एवं 5 स्टैटिक	2.58	समस्त जनरेटरों की आपूर्ति पूर्ण गयी है। इन जनरेटरों का ट्राय किया जा रहा है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WWM01D	देहरादून में 68mld के सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का अभिकल्पन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण तथा चालू करना। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 27.03.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 26.03.2012	57.42	एस.टी.पी. में 50मी. रिटेनिंग वॉल 120 मी. कम्पाउण्ड वॉल का किया जा चुका है। ब्लोअर रू फाउण्डेषन का कार्य प्रगति प कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एस.बी.आर. टैं ड्राईंग डिज़ाईन पी.आई.यू. को अ हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WWM02D	देहरादून के कारगी क्षेत्र में सीवरेज लाईनों का बिछाना, परीक्षण तथा चालू करना। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 16.08.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 15.08.2012 ● `हरादून के कारगी क्षेत्र में लगभग 80 किमी0 की सीवर लाईन(ट्ंक तथा लेटरल) का बिछाना।	39.22	500मीटर सीवर लाईन बिछायी ज है। कार्य प्रगति पर है।
	WWM03D	देहरादून में कारगी क्षेत्र के सीवर्ड क्षे में सीवरेज लाईनों का बिछाना, परीक्ष तथा चालू करना।	16.28	800 मीटर सीवर लाईन बिछा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 09.08.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 08.08.2012 ● `हरादून के कारगी क्षेत्र में लगभग 40 किमी0 की सीवर लाईन(लेटरल) का बिछाना।		
	WSS01 H	हरिद्वार में पम्पग्रहों एवं पम्प इकाई का नवीनीकरण। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.08.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 11.05.2011	3.23	पैकेज का अनुबन्ध गठित किय चुका है। Site investigation, shifting, office establish confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। तकनीकी डि

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		● म्पिंग प्लान्टों की संख्या 33(23VT+8H+2S)		एवं डेटा पर अनुमोदन दिया जा चु
	WSS01 N	नैनीताल में पुराने पंम्पिंग यूनिट व बदलना तथा नये पंम्पिं प्लान्ट/हाउस का निर्माण तथा न टयूबवेल का निर्माण। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.09.2010 ●	11.70	पैकेज का अनुबन्ध गठित किय चुका है तथा Site investigation, shifting, office establish confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। QAP पूर्ण कि चुका है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		ार्य पूर्ण होने की तिथि 19.09.2012 ● नये पम्पिंग हाउस, 4 नये टयूवैल, एव इनफिलटेस्न वैल एवं 2 संपों का निर्माण। ● पम्पिंग स्टेषनों का जिर्णोधार तथा पम्पिंग प्लान्टों की स्थापना।		
	WSS02 N	नैनीताल के आलसेन्ट जोन जलापूर्ति के अन्तर्गत वितरण/राइजिं मैन के कार्य। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ● नये पम्पिंग प्लान्ट की स्थापना। ●	4.33	3.6 कि.मी. पाईपों की आपूर्ति क चुकी है। निर्माण कार्य प्रारम्भ कि चुका है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		.35 किमी0 राइजिंग मेंन की स्थापना। ● .2 किमी0 की डिस्ट्रिब्यूषन लाईन। ● 50 KL CWR की स्थापना। ● उसक softening प्लान्ट की स्थापना		
	WSS03 N	नैनीताल में जलापूर्ति के अन्तर्गत न राइजिंग मेन का डालना तथा पुरान राइजिंग मेन एवं स्टील टैंको व बदलना। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ● 2 किमी0 राइजिंग मेंन का बदलना। ● पुराने स्टील टैंको का बदला	17.63	400 मी. पाईप लाईन बिछाया ज है। 5 कि.मी. के पाईप तथा 100 ि स्पेषल्स की आपूर्ति पूर्ण की जा चु स्टील टैंकों के निर्माण हेतु मैटिरिय खरीद की जा रही है तथा इस उप पर कार्य प्रारम्भ कर लिया जा

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		जाना(60-535KL)। ● 4 Electro Chlorinator(2 mld each) की खरीद। ● 5 Electro Magenetic Flow meter की खरीद।		
	WSS04N	नैनीताल में जलापूर्ति के अन्तर्गत जलाषयों तथा स्प्रिंग कलेक्टिंग चैम्बर का निर्माण । ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ●	5.27	स्नो व्यू पर एक जलाषय का प्रारम्भ हो चुका है तथा अन्य जलाष निर्माण का कार्य इसी माह प्रारम्भ लिया जायेगा।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		1 RCC CWR(250-900KL) की स्थापना। • स्प्रिंग कलेक्टिंग चैम्बरों का निर्माण।		
		कुल योग	**212.97**	

ट्रैन्च – 1 के प्रस्तावित अन्य कार्यो का विवरण					
1		देहरादून, हरिद्वार व नैनीताल की जी.आई.एस. प्रॉपर्टी टैक्स मैंपिंग	1.45	आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट तैयार है तथा इसव निविदायें आमंत्रण का कार्य मार्च, 2011 कर लिया जायेगा।	
2		**कैपेसिटी बिल्डिंग**			

		(i) फाईनेंसिंग एवं इंस्टीट्यूषनल सुधार	**7.90**	• ाफ्ट् म्यूनिसिपल एकाउन्ट्स मैनुअल तैया कर शासन को प्रेषित कर दिया गया है। • ाफ्ट् म्युनिसिपल एक्ट तैयार कर लिया गय है। • 4th CAA के आधार पर Devolution Pla तैयार किया जा चुका है जिसके क्रियान्वय पर शीघ्र ही प्रयास किया जायेगा। • न्य रिफार्म से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर हैं।	
		(ii) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन जागरूकता	**2.25**	एन.जी.ओ. का चयन कार्य जल्द ही पूर्ण क लिया जायेगा।	
		(iii) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट स्टेट्जी एण्ड प्लानिंग	**1.38**	राज्य स्तरीय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया ज चुका है तथा आख्या कार्य प्रगति पर है।	
		(iv) मलिन बस्ती सुधार	**0.47**	• ाज्य स्तरीय सेंसस सर्वेक्षण पूर्व किया ज चुका है तथा डाटा ऐन्ट्री कार्य प्रगति पर है। • राज्य मलिन बस्ती नीति का प्रथम स्वरू शासन को प्रेषित किया जा चुका है। • ाज्य मलिन बस्ती परिभाषा एवं मानकों क स्वरूप शासन को प्रेषित किया गया जिसक शासनादेश जारी किया जा चुका है।	
		(v) ट्रेनिंग एवं स्टडी टूर	**2.31**	चालू वर्ष के लिए ट्रेनिंग कैलेण्डर तैयार क लिया गया है। कर्नाटक के शहरी विका परियोजना के स्टडीर टूर के लिए पी.एम. /पी.आई.यू. से अधिकारियों का भ्रमण अप्रै 2011 में प्रस्तावित है।	

पूर्व मे स्वीकृत परियोजनाओ का विवरण

(धनराशि

करोड़ रूपये में)

		स्वीकृत परियोजना लाग			निर्मित होने वाले भवनों की संख्य	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त			परियोजना समाप्त होने की तिथि
				कु परि जन लाग			धनराशि		
				3	5		0.66		अगस्त, 201
				5	17		2.20		मार्च, 2010

	योग			8	23		2.8			

भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओ की माह मार्च, 2010 में सचिव, आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित सी0एस0एम0सी0 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। जिनका विवरण निम्नवत् है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(धनराशि करोड़ रूपये में)

	स्वीकृ परियोज	स्वीकृत परियोजना लागत				अवमुक्त प्रथम किश्त			परि जन समाप होने तिथि	टिप्पणी
				कुल परियोजन लागत		क				
	महुआ ाबरा			9.25		म र्च 201 0			अग स्त, 201	72 मका निमार्णाधीन 30 पूर्ण।
	महुआ ड़ागंज			11.8		म र्च 201 0			अग स्त, 201	187 मकान निमार्णाधीन 20 पूर्ण।
	दिनेश			11.7		म			अग	153 मका

	र					र्च 20 0			स्त, 201	निमार्णाधीन 15 पूर्ण।
	काशीप् र			11.9		म र्च 20 0			अग स्त, 201	223 मका निमार्णाधीन
	लालकु आ			3.59		म र्च 20 0			अग स्त, 201	फाउन्डेशन का प्रारम्भ
	पिथौर गढ़			10.9		म र्च 20 0			अग स्त, 201	126 मका निमार्णाधीन 12 पूर्ण।
	कालाढ़ गी			10.4		ज न 20 0			अग स्त, 201	169 मका निमार्णाधीन 12 पूर्ण।
	किच्छा			5.63		अ गस , 20 0			अग स्त, 201	65 मका निमार्णाधीन 9 पूर्ण।
	चम्पाव			3.81		अ गस , 20 0			अग स्त, 201	फाउण्डेशन का प्रारम्भ
	मसूरी			5.10		ज् लाइ 20 0			अग स्त, 201	फाउण्डेशन का प्रारम्भ
	अल्मोड़			8.33		ज् लाइ 20 0			अग स्त, 201	25 मका निमार्णाधीन 33 पूर्ण।
	जसपुर (फेस–1			6.30		सि तम्ब र, 20 0			अग स्त, 201	15 मकान निमार्णाधीन

	जसपुर (फेस–2			1.57		सितम्बर, 2010			अगस्त, 2011	33 मकान निमार्णाधीन
	लण्ढौर (फेस–1			10.1		सितम्बर, 2010			अगस्त, 2011	12 मकान निमार्णाधीन
	लण्ढौर (फेस–2			2.58		सितम्बर, 2010			अगस्त, 2011	82 मकान निमार्णाधीन 15 पूर्ण।
	हल्द्वानी			13.4		फरवरी 2011			अगस्त, 2011	15 मकान निमार्णाधीन
	हल्द्वानी – काठगोदाम			11.8		फरवरी 2011			अगस्त, 2011	20 मकान निमार्णाधीन
	विकास नगर			3.34		सितम्बर, 2010			अगस्त, 2011	26 मकान का कार्य निर्माणाधीन
	मंगलौर			13.4		फरवरी 2011			अगस्त, 2011	33 मकान निमार्णाधीन
	योग			**155.42**						

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 परियोजना के अन्तर्गत प्रगतिशील कार्यो के छायाचित्र

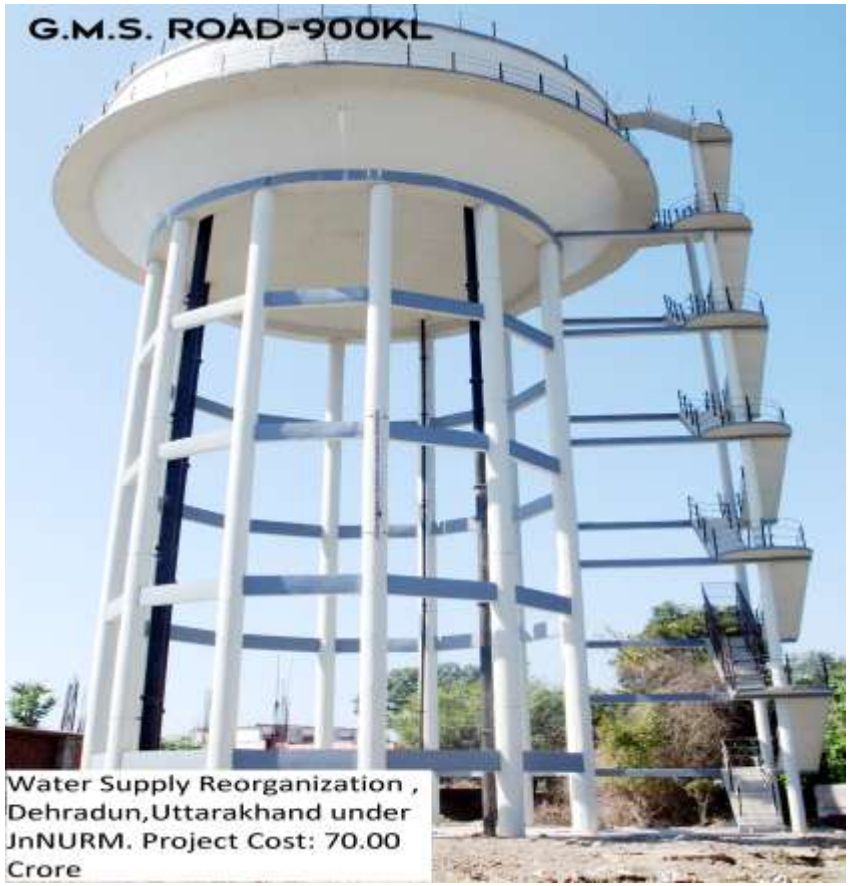

Water Supply Reorganization , Dehradun,Uttarakhand under JnNURM. Project Cost: 70.00 Crore

HARIDWAR
BHOPATWALA
OVERHEAD TANK
Water Supply Reorganization ,
Haridwar,Uttarakhand under JnNURM. Project
Cost: 47.84 Crore

HARIDWAR BHOPAT WALA
INFILTRATION WELL
Water Supply Reorganization ; Haridwar,Uttarakhand under
JnNURM. Project Cost: 47.84 Crore

Sewerage System Nainital. Project Cost Rs 19.6 Cr

Water Supply Reorganization , Nainital. Project Cost Rs 5.47 Cr.

BSUP- Shati Kusth Ashram, Dehradun. Project Cost: Rs 1.37 Cr.

BSUP- Pandey Wala, Haridwar. Project Cost: Rs 4.34 Cr.

IHSDP Photographs

Photo of Construction Activities at Pauri
Project Cost Rs: 4.52 Cr.

IHSDP Photographs

Photo of Construction Activities at Srinagar
Project Cost Rs.: 1.33 Cr.

बिन्दु संख्या :–5

शहरी विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजनागत मद में प्राविधान और स्वीकृतियों की स्थिति तथा व्यय विवरण

(अनुपूरक सहित)

(धनराशि लाख रू

क्र सं0	अनुदान सं0–13, 30 एवं 31 , लेखा शीर्षक /योजना	प्रस्तावित परिव्यय	आय–व्य क में योजनावार प्राविधान	स्वीकृ	व्यय विवरण
1	2217–03–191–01–0101–20 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (केन्द्र सहायतित)	81.9	67.7	30.3	10
2	2217–03–800–01–0102–20 कम लागत के व्यक्तिगत शौचालय (केन्द्र सहायतित)	53.1	147.6	0.0	0
3	2217–03–191–03–0302–42 मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन	485.0	43.0	0.0	0
4	2217–03–191–03–0303–20 **(UA-URIF)** **उत्तरांचल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि**	500.0	125.0	0.0	0

5	2217–03–191–03–0305–20 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	1862.0	820.7	154.6	73
6	2217–03–191–03–0308–20 संक्रमण शील क्षेत्रों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं क विकास	25.0	0.0	0.0	0
7	2217–03–191–03–0309–20 व 42 नगरीय क्षेत्रों में सार्वभौम रोजगार योजना	22.5	18.1	0.0	0
8	2217–191–97–9701–16 **(बाह्य सहायतित)** **नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान**	11724.	11506.	2669.	3003
9	2217–03–800–01–0105–20 राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (NURM) (केन्द्र सहायतित)	21402.	18772.	311.9	0
10	2217–03–191–01–0102–20 आवास एवं मलिन बस्ती सुधार (IHSDP) (केन्द्र सहायतित)	4344.0	5729.6	4393.	1350
11	2217–03–800–01–0104–42 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण UIDSSMT	1363.7	3536.2	0.0	0
12	2217–001–08–42 व 16 परियोजनाओं की प्रारंभिक तैयारियां एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु	100.0	45.4	45.4	0
13	2217–03–191–03–0306–42 कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था	0.0	0.0	0.0	0
14	2217–03–088–04–22 कंप्युटराईजेशन एण्ड जी.आई.एस.	150.0	25.0	0.0	0
15	2217–80–8..–01–0107–20 हरिद्वारा कुंभ मेला हेतु अवस्थापना विकास	0.0	1500.0	0.0	0
16	2217–03–800–01–0106–20 बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर (BSUP) (NURM व अन्तर्गत केन्द्र सहायतित)	1968.9	4461.0	1305.	90
17	2217–04–001–02 शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद	0.0	19.5	19.5	17
18	2217–80–800–03 हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान	0.0	173.3	173.3	163
19	2217–80–800–06 मेला प्राधिकरण का अधिष्ठान	0.0	13.3	13.3	0
20	2217–80–800–05 नगर पालिका परिषद, भवाली को अनुदान	0.0	50.0	50.0	25
	कुल योग	**44082.**	**47054.**	**9168.**	**4732.**

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा संचालित योजनाऐं :–

1– स्वर्ण जयंती

शहरी रोजगार योजना

केन्द्र पुरोनिधानित इस योजनान्तर्गत संषोधित दिषा–निर्देषा के अुनसार वर्ष 2010–11 में केन्द्रांष तथा राज्यांष का अनुपात 90:10 है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांष के रूप में रू0 546.34 लाख की धनराषि आवंटित की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांष रू0 546.34 लाख के सापेक्ष राज्यांष रू0 60.70 लाख की धनराषि अवमुक्त की गयी है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजनगार योजना की उपयोजना निम्नवत् है :–

1– स्वतः

रोजगार योजना :–

इसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में निवासरत बेरोजगार एवं आंषिक रूप से बेरोजगार व्यक्ति को अपना निजी व्यवसाय की व्यवस्था हेतु अधिकतम रू0 2,00,000/– तक की परियोजना लागत के सापेक्ष जिला नगरीय विकास अभिकरण/नगर निकाय द्वारा 25 प्रतिषत अनुदान (अधिकतम राषि 50,000/–) दिये जाने का प्राविधान है, जबकि 05 प्रतिषत अंषदान लाभार्थी को भी देना आवष्यक है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू0 316.80 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 792 लाभार्थी निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2011 तक रू0 208.55 लाख धनराषि व्यय कर 698 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

2– स्वतः

रोजगार प्रषिक्षण कार्यक्रम :–

इस योजना के अंतर्गत निर्धन पात्र लाभार्थियों को आवष्यकतानुसार संबंधित रोजगार में प्रषिक्षण दिलाये जाने का प्राविधान है। जिसकी व्यवस्था डूडा/नगर निकाय द्वारा आई0टी0आई0/राजकीय संस्थान सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से (मास्टर क्राफ्ट मैन की सहायता से) की जाती है। प्रषिक्षण की अवधि तीन से छः माह होती है। जिसमें कम से कम 300 घण्टे प्रषिक्षण होना अनिवार्य है।

योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत प्रषिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू0 290.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 2900 लाभार्थी निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष रू0 43.18 लाख धनराषि व्यय कर 1598 लाभार्थियों को माह फरवरी, 2011 तक प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा शेष लाभार्थियों का प्रषिक्षण का कार्य माह मार्च 2011 तक पूर्ण हो जायेगा।

3—
नगरीय

मजदूरी योजना :—

योजनान्तर्गत मलिन बस्ती वासियों को जन—मूलभूत आवष्यकतायें जैसे :— सड़क/नाली, पेयजल, सामुदायिक केन्द्र, नाला/सीवर, स्ट्रीट लाईट, सामुदायिक शौचालय आदि का कार्य कराये जाने का प्राविधान है। इन कार्यो के माध्यम से बेरोजगार निर्धन को मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाना योजना का मुख्य उद्देष्य है।

योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देष्य से मलिन बस्तियों में सड़क, नाली, खड़जा आदि का निर्माण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू0 277.97 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 74056 मानवदिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2011 तक रू0 219.97 लाख धनराषि व्यय कर 80940 मानवदिवस सृजित किये जा चुके है।

4— थ्रिफ्ट एण्ड

क्रेडिट योजना :—

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत नगरीय निर्धन महिलाओं में बचत की आदर पैदा करने के उद्देष्य से उनकी बचत—ऋण समितियों का गठन कराये जाने का प्राविधान है, जिसमें वे आम सहमति से बचत द्वारा एकत्रित धनराषि में से अपनी छोटी—छोटी आवष्यकताओं हेतु ऋण प्राप्त कर सके। इन समूहों को एक वर्ष तक क्रियाषील रहने के पष्चात् बचत की गयी धनराषि के समकक्ष (अधिकतर प्रति सदस्य एक हजार रूपये तक) मैचिंग ग्राण्ट प्रदान की जाती है। ताकि समूहों के सषक्तिकरण के साथ—साथ उन्हें रोजगार परक कार्यक्रमों से जोड़ते हुए दीर्धकाल में स्वावलम्बी बनाया जा सके। योजनान्तर्गत 10 से 25 महिलाओं तक से समूह का गठन किये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु वित्तीय लक्ष्य रू0 43.75 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 175 समूह निर्धारित किये गये है जिसके सापेक्ष माह फरवरी 2011 तक रू0 3.83 लाख धनराषि व्यय कर 40 समूहों का गठन किया जा चुका है।

2— कम लागत

के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना (आई0एल0सी0एस0) :—

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010—11 में कम लागत के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना आरम्भ की गयी है, जिसका उद्देष्य शुष्क शौचालयो को जल प्रवाहित शौचाल में परिवर्तित करना तथा शौचालय रहित घरों में शौचालय का निर्माण करना है।

योजनान्तर्गत केन्द्रांष 75 प्रतिषत, राज्यांष 15 प्रतिषत एवं लाभार्थी अंषदान 10 प्रतिषत निर्धारित है। सर्वेक्षण में 06 नगर निकायों क्रमषः देहरादून, मंगलौर, रूड़की, हल्द्वानी, चमोली एवं रूद्रपुर के लिए कुल 1613 यूनिट शुष्क शौचालय पाये गये। भारत सरकार द्वारा उक्त 1613 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु कुल रू0 1.63 करोड़ की डी0पी0आर0 स्वीकृत की गयी है। भारत

सरकार द्वारा केन्द्रांष के रूप में रू0 123.00 लाख अवमुक्त किया गया है और राज्यांष रू0 24.60 लाख अवमुक्त किया गया है। योजनान्तर्गत कुल 1204 यूनिट शौचालयों पर निर्माण पूर्ण हो चुका है। नगर निगम, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत 761 यूनिट शौचालय के सापेक्ष 409 यूनिट शौचालयों का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं कर लिया गया है।

Investment Program Management Unit
Uttarakhand Urban Sector Development Investment Program
Government of Uttarakhand
New ISBT Complex, Hardwar By-Pass, Majra, Dehradun
Telephone +91-135-2643894, Tele-fax +19-135-2643895
Email: uusdip@gmail.com

उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तृत विवरण (ए0डी0बी0)

Loan No-2410:IND

1–एशियन विकास बैंक (ए0डी0बी0) सहायतित परियोजनायें :–

मूलभूत बेहतर शहरी संरचना व सेवाओं की आवश्यकताओं की प्रर्ति व उचित प्रबन्धन प्रदान कर क्षेत्र की सामाजिक, अर्थिक व गरीबी कम करने की दिशा में सहयोगी है। इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक (ADB) ने नगरीय विकास की भूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड नगरीय विकास निवेश कार्यक्रम के लिए लगभग 1400 करोड की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2–कार्यक्रम के उद्देश्य :

कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

•भारत सरकार के विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के विकास कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना।

•प्रदेश की समाजिक व आर्थिक क्षेत्रीय विकास नीति के अनुसार स्थानीय विकास में सहयोग प्रदान करना

•पर्यावरण में सुधार व गरीबी उत्थान कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना

•शहरी विकास की योजनाओं का निर्धारण, कुशल प्रबंधन, गवर्नेन्स इत्यादि सम्बन्धित विषयों पर क्षमतावर्धन।

1.योजना की निर्धारित अवधि–2008–2016

2.योजना की कुल लागत–लगभग रू0 2000 करोड

3.ए0डी0बी0 ऋण की धनराशि–लगभग रू0 1400 करोड

4.राज्य सरकार का अशंदान–लगभग रू0 600 करोड

5.योजना के चरण [Tranches] –सम्पूर्ण योजना चार चरणों में विभाजित है। प्रत्येक चरण की अनुमानित लागत का विवरण निम्नवत है।

चरण सं0अवधि अनुमानित लागत ए0डी0बी0 ऋण राज्यांश

प्रथम2008–2012लगभग रू0 344 करोडलगभग रू0 240 करोड लगभग रू0 104 करोड

द्वितीय2009–2013लगभग रू0 312 करोड लगभग रू0 220 करोड लगभग रू0 92 करोड

तृतीय2010–2014लगभग रू0 584 करोड लगभग रू0 408 करोड लगभग रू0 176 करोड

चतुर्थ2011–2016लगभग रू0 760 करोड लगभग रू0 532 करोड लगभग रू0 228 करोड

योग लगभगरू0 2000 करोडरू0 1400 करोडरू0 600 करोड

3– योजना में सम्मिलित नगर/स्थान तथा चरणवार कराये जाने वाले कार्य–

योजना के अन्तर्गत 31 नगरों/स्थानों का चयन किया गया है। प्रत्येक चरण [tranch] में सम्मिलित नगरों/स्थानों तथा वहां पर कराये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नांकित है –

ट्राँच – 1

कार्य		**नगर/स्थान का नाम**
वाटर सप्लाई	–	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल
सीवरेज	–	देहरादून

ट्राँच – 2

वाटर सप्लाई	–	देहरादून, नैनीताल, रूद्रपुर
सीवरेज	–	रूद्रपुर
मलिन बस्त सुधार	–	देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रूद्रपुर

ट्राँच – 3

वाटर सप्लाई	–	रूड़की, श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाषी, गोपेष्वर, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी, काषीपुर, किच्छा, रामनगर
सीवरेज	–	रूड़की, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ चम्पावत, हल्द्वानी, काशीपुर, किच्छा, रामनगर, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट।

ट्राँच – 4

शहरी सड़क तथ	रूड़की, नई टिहरी, श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाशी, गोपेश्वर, रूद्रप्रयाग, रूद्रपुर, काशीपुर, अल्मो

.	यातायात सुधार ए	बागेष्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, हल्द्वानी
	ठोस अपषिष्ट प्रबंधन	
.	ठोस अपषिष प्रबंधन (Solid Waste Management)	हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट, जोशीमठ, रूड़की, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनथ, मसूर कोटद्वार, मंगलौर, बाजपुर, रामनगर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज।

प्रथम ट्रांच के प्रस्तावित कार्यों का विवरण तथा भौतिक स्थिति

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WSS01 D	देहरादून स्थित कोर एरिया जलापूर्ति हेतु वितरण प्रणाली क बिछाना। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 16.08. 2010 ●	39.15	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चु लगभग 15 कि.मी. की लाईन डाल क्षेत्र में लक्ष्मी रोड पर बिछायी ज है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		ार्य पूर्ण होने की तिथि 15.08. 2012 ● डस्ट्रीब्यूषन पाईप लाईन की लम्बाई 168 किमी0		
	WSS02 D	देहरादून में बॉदल नदी श्रोत से दिलाराम बाजार स्थित जल कल तक कच्चा पानी लाने हेतु पाईप लाइन बिछाना। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 30.01.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 29.04.2011 ● ाईप लाईन की लम्बाई 14 किमी0	11.35	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया लगभग 6.5 कि.मी. की लाईन चुकी है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WSS03 D	देहरादून में मौजूदा पेयजल आपू व्यवस्था में पम्प ईकाईयों एवं वाल्व बिजली के उपकरणों को बदलना तथ पम्प हाउसों का जीर्णोधार। ● र्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.08.2010 ● र्य पूर्ण होने की तिथि 11.05.2011 ● म्पिंग प्लान्टों की संख्या 52(38 S+14H	4.81	पैकेज का अनुबन्ध गठित किय चुका है। Site investigation, shifting, office establish confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। तकनीकी डि एवं डेटा पर अनुमोदन दिया जा चु 23 मोटरों की आपूर्ति की जा चु तथा इसी माह पम्पों की आपूर्ति पू ली जायेगी।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WSS04D	देहरादून नगर में पेयजल व्यवस्था हे 15 नग स्टैटिक एवं मोबाईल जनरेटर की व्यवस्था। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 05.06.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 04.12.2011 ● 0 मोबाईल जनरेटर एवं 5 स्टैटिक	2.58	समस्त जनरेटरों की आपूर्ति पूर्ण गयी है। इन जनरेटरों का ट्राय किया जा रहा है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WWM01D	देहरादून में 68mld के सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का अभिकल्पन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण तथा चालू करना। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 27.03.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 26.03.2012	57.42	एस.टी.पी. में 50मी. रिटेनिंग वॉल 120 मी. कम्पाउण्ड वॉल का किया जा चुका है। ब्लोअर रू फाउण्डेषन का कार्य प्रगति प कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एस.बी.आर. टैं ड्राईंग डिज़ाईन पी.आई.यू. को अ हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
	WWM02D	देहरादून के कारगी क्षेत्र में सीवरेज लाईनों का बिछाना, परीक्षण तथा चालू करना। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 16.08.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 15.08.2012 ● `हरादून के कारगी क्षेत्र में लगभग 80 किमी0 की सीवर लाईन(ट्रंक तथा लेटरल) का बिछाना।	39.22	500मीटर सीवर लाईन बिछायी ज है। कार्य प्रगति पर है।
	WWM03D	देहरादून में कारगी क्षेत्र के सीवर्ड क्षे में सीवरेज लाईनों का बिछाना, परीक्ष तथा चालू करना।	16.28	800 मीटर सीवर लाईन बिछा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 09.08.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 08.08.2012 ● `हरादून के कारगी क्षेत्र में लगभग 40 किमी0 की सीवर लाईन(लेटरल) का बिछाना।		
	WSS01 H	हरिद्वार में पम्पग्रहों एवं पम्प इकाई का नवीनीकरण। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.08.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 11.05.2011	3.23	पैकेज का अनुबन्ध गठित किय चुका है। Site investigation, shifting, office establish confirmatory survey का कार्य किया जा चुका है। तकनीकी डि

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		● म्पिंग प्लान्टों की संख्या 33(23VT+8H+2S)		एवं डेटा पर अनुमोदन दिया जा चु
	WSS01 N	नैनीताल में पुराने पंम्पिंग यूनिट व बदलना तथा नये पंम्पिं प्लान्ट/हाउस का निर्माण तथा न टयूबवेल का निर्माण। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 12.09.2010 ●	11.70	पैकेज का अनुबन्ध गठित किय चुका है तथा Site investigation, shifting, office establish confirmatory survey का कार किया जा चुका है। QAP पूर्ण कि चुका है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		ार्य पूर्ण होने की तिथि 19.09.2012 ● नये पम्पिंग हाउस, 4 नये टयूवैल, एव इनफिलटेस्न वैल एवं 2 संपों का निर्माण। ● पम्पिंग स्टेषनों का जिर्णोधार तथा पम्पिंग प्लान्टों की स्थापना।		
	WSS02 N	नैनीताल के आलसेन्ट जोन जलापूर्ति के अन्तर्गत वितरण/राइजिं मैन के कार्य। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ● नये पम्पिंग प्लान्ट की स्थापना। ●	4.33	3.6 कि.मी. पाईपों की आपूर्ति क चुकी है। निर्माण कार्य प्रारम्भ कि चुका है।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		.35 किमी0 राइजिंग मेंन की स्थापना। ● .2 किमी0 की डिस्ट्रिब्यूषन लाईन। ● 50 KL CWR की स्थापना। ● उसक softening प्लान्ट की स्थापना		
	WSS03 N	नैनीताल में जलापूर्ति के अन्तर्गत न राइजिंग मेन का डालना तथा पुरान राइजिंग मेन एवं स्टील टैंको व बदलना। ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ● 2 किमी0 राइजिंग मेंन का बदलना। ● पुराने स्टील टैंको का बदला	17.63	400 मी. पाईप लाईन बिछाया ज है। 5 कि.मी. के पाईप तथा 100 ि स्पेषल्स की आपूर्ति पूर्ण की जा चु स्टील टैंकों के निर्माण हेतु मैटिरिय खरीद की जा रही है तथा इस उप पर कार्य प्रारम्भ कर लिया जा

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		जाना(60-535KL)। ● 4 Electro Chlorinator(2 mld each) की खरीद। ● 5 Electro Magenetic Flow meter की खरीद।		
	WSS04N	नैनीताल में जलापूर्ति के अन्तर्गत जलाषयों तथा स्प्रिंग कलेक्टिंग चैम्बर का निर्माण । ● ार्य प्रारम्भ होने की तिथि 20.09.2010 ● ार्य पूर्ण होने की तिथि 19.03.2012 ●	5.27	स्नो व्यू पर एक जलाषय का प्रारम्भ हो चुका है तथा अन्य जलाष निर्माण का कार्य इसी माह प्रारम्भ लिया जायेगा।

	पैकेज कोड	पैकेज का विवरण (पुनरीक्षित)	कार्य की लागत भारतीय रूपये (करोड़ में)	वर्तमान भौतिक स्थिति
		1 RCC CWR(250-900KL) की स्थापना। • स्प्रिंग कलेक्टिंग चैम्बरों का निर्माण।		
		कुल योग	**212.97**	

ट्रैन्च – 1 के प्रस्तावित अन्य कार्यो का विवरण					
1		देहरादून, हरिद्वार व नैनीताल की जी.आई.एस. प्रॉपर्टी टैक्स मैंपिंग	1.45	आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट तैयार है तथा इसव निविदायें आमंत्रण का कार्य मार्च, 2011 कर लिया जायेगा।	
2		**कैपेसिटी बिल्डिंग**			

		(i) फाईनेंसिंग एवं इंस्टीट्यूषनल सुधार	**7.90**	• ाफ्ट् म्यूनिसिपल एकाउन्ट्स मैनुअल तैया कर शासन को प्रेषित कर दिया गया है। • ाफ्ट् म्युनिसिपल एक्ट तैयार कर लिया गय है। • 4th CAA के आधार पर Devolution Pla तैयार किया जा चुका है जिसके क्रियान्वय पर शीघ्र ही प्रयास किया जायेगा। • न्य रिफार्म से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर हैं।	
		(ii) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन जागरूकता	**2.25**	एन.जी.ओ. का चयन कार्य जल्द ही पूर्ण क लिया जायेगा।	
		(iii) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट स्टेट्जी एण्ड प्लानिंग	**1.38**	राज्य स्तरीय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया ज चुका है तथा आख्या कार्य प्रगति पर है।	
		(iv) मलिन बस्ती सुधार	**0.47**	• ाज्य स्तरीय सेंसस सर्वेक्षण पूर्व किया ज चुका है तथा डाटा ऐन्ट्री कार्य प्रगति पर है। • राज्य मलिन बस्ती नीति का प्रथम स्वरू शासन को प्रेषित किया जा चुका है। • ाज्य मलिन बस्ती परिभाषा एवं मानकों क स्वरूप शासन को प्रेषित किया गया जिसक शासनादेश जारी किया जा चुका है।	
		(v) ट्रेनिंग एवं स्टडी टूर	**2.31**	चालू वर्ष के लिए ट्रेनिंग कैलेण्डर तैयार क लिया गया है। कर्नाटक के शहरी विका परियोजना के स्टडीर टूर के लिए पी.एम. /पी.आई.यू. से अधिकारियों का भ्रमण अप्रै 2011 में प्रस्तावित है।	

द्वितीय ट्रांच के प्रस्तावित कार्यों का विवरण तथा भौतिक स्थिति

क्रमांक	पैकेज	पैकेज का विवरण	३	वर्तमान स्थिति

	कोड		नुम नत ला त रू कर ड़	
	WSS05 D	देहरादून में वाटर ऑप्टिमाईजेषन ए मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत राईजिंग मेन एवं फीड मेन का बिछाया जाना।	3 00	प्रस्तावित कार्यों से सम्बन्धित कन्सैप्ट नो तैयार कर फरवरी 2010 में ए.डी.बी. को उपलब करा दिये गए हैं। इन कार्यों की डी.पी.आ तैयार की जा रही हैं वर्तमान में सर्वेक्षण का पूर्ण हो चुका है डी.पी.आर. डी0एस0सी0 द्वा जमा करा दी गई तथा आई0पी0आई0यू0 द्वा अध्ययन किया जा रहा है।
	WSS06 D	देहरादून में दिलाराम वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान एवं शहनशाही आश्रम वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान का नवीनीकरण एवं उच्चीकरण।	2 00	प्रस्तावित कार्यों से सम्बन्धित कन्सैप्ट नो तैयार कर फरवरी 2010 में ए.डी.बी. को उपलब करा दिये गए हैं। इन कार्यों की डी.पी.आ तैयार की जा रही हैं वर्तमान में सर्वेक्षण का पूर्ण हो चुका है डी.पी.आर. डी0एस0सी0 द्वा जमा करा दी गई तथा आई0पी0आई0यू0 द्वा अध्ययन किया जा रहा है।
	WSS07 D	देहरादून में 13 जोनों में जलापूर्ति हे वितरण प्रणाली का बिछाना।	3 5	डी.पी.आर. पी.आई.यू. को अनुमोदन हेतु जम की जा चुकी है।
	WSS08 D	देहरादून में मॉसी फॉल से शहनशाही आश्र तक रॉ वाटर मेन का बिछाया जाना ए सॉफ्टनिंग प्लान्ट का संस्थापन।	2 00	डी.पी.आर. का विरचन भी शीघ्र ही पूर्ण क लिया जायेगा।
	WSS09 D	देहरादून के कोर एरिया में वाटर सप्ला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बिछाया जान टैस्टिंग एवं कमीशनिंग।	3 3	डी.पी.आर. पी.आई.यू. को अनुमोदन हेतु जम की जा चुकी है।
	WSS10 D	देहरादून के छुटे हुए एरिया में वाटर सप्ला डिस्ट्रीब्यूषन सिस्टम का बिछाया जाना, टैस्टिं एवं कमीषनिंग।	4 2	डी.पी.आर. पी.आई.यू. को अनुमोदन हेतु जम की जा चुकी है।
	WSS11 D	पम्पिंग स्टेषन्स में स्काडा सिस्टम व संस्थापन।	7 00	कॉन्सेप्ट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया ज चुका है।
	WSS12 D	देहरादून में घरेलू वाटर मीटर की सप्लाई ए संस्थापन।	7 00	कॉन्सेप्ट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया ज चुका है।
	WWM 4D	देहरादून के कारगी जोन के टी.एच.डी.सी क्षेत्र में सीवर नेटवर्क सिस्टम का बिछाय जाना, टैस्टिंग एवं कमीशनिंग।	1 93	डी.पी.आर. टेक्नीकल कमेटी के अनुमोदन हे तैयार है।

	WSS02 HD	हरिद्वार में स्काडा सिस्टम के अन्तर्ग ट्यूबवैल एवं अन्य पम्पिंग प्लान्टस क ऑटोमाईजेशन	70 00	कॉन्सेप्ट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया ज चुका है।
	WSS03 HD	हरिद्वार में घरेलू वाटर मीटर एवं बल्क वाट मीटर की सप्लाई एवं संस्थापन।	75 00	कॉन्सेप्ट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया ज चुका है।
	WSS01 RKE	रूड़की शहर के वाटर सप्लाई का बढ़ाय जाना एवं पुनर्गठन।	43 00	ड्राफ्ट् मास्टर प्लान अनुमोदन हेतु जमा कराय जा चुका है। डी.पी.आर. का विरचन अन्ति चरणों में है।
	WWM 1RKE	रूड़की शहर के वर्तमान सीवर नेटवर्क क नवीनीकरण एवं छुटे हुए क्षेत्रों में सीवर नेटव का बिछाया जाना।	1 5.0	डी.पी.आर. का विरचन अन्तिम चरणों में है।
	WWM 2RKE	रूड़की शहर में 34 एम.एल.डी. सीवे ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण।	15 50	डी.पी.आर. का विरचन अन्तिम चरणों में है।
	WSS05 N	नैनीताल शहर में डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स क बिछाया जाना एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	30 27	डी.पी.आर. का विरचन किया जा चुका है तथ अनुमोदन हेतु पी.आई.यू. को जमा कराया जा चुका है।
	WSS06 N	नैनीताल में घरेलू वाटर मीटर ए व्यावसायिक वाटर मीटर की सप्लाई ए संस्थापन।	2 00	डी.पी.आर. का विरचन किया जा चुका है तथ अनुमोदन हेतु पी.आई.यू. को जमा कराया ज चुका है।
	WSS07 N	नैनीताल हेतु सभी पम्पिंग प्लान्टस का ज एस.एम. बेस्ड स्काडा सिस्टम द्वा ऑटोमाईजेशन	5 00	कॉन्सेप्ट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया ज चुका है। डी.पी.आर. डी0एस0सी0 द्वारा जम करा दी गई।
	WSS08 N	नैनीताल हेतु सॉफ्टनिंग प्लान्ट का डिजाई संस्थापन एवं तत्सम्बन्धित कार्य	0 90	कॉन्सेप्ट नोट डी.एस.सी.द्वारा जमा कराया ज चुका है।
	WSS01 AM	अल्मोड़ा की वाटर सप्लाई क ऑप्टोमाईजेशन एवं पुनर्गठन।	10 50	मास्टर प्लान डी.एस.सी.द्वारा पी.आई.यू. क जमा कराया जा चुका है जिस पर आख्य वांछित है। डी.पी.आर. डी0एस0सी0 द्वारा जम करा दी गई।
	WWM 1RM	अल्मोड़ा के जोन 2 व 4 में सीवर लाईन क बिछाया जाना, पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ए उसकी राईजिंग मेन का बिछाया जाना।	7 50	मास्टर प्लान डी.एस.सी.द्वारा फरवरी माह त पी.आई.यू. को जमा कराया जायेगा तथा डी.पी आर.विरचन का कार्य मार्च तक पूर्ण कर लिय जायेगा।
	WWM 2A	अल्मोड़ा में 9.75 एम.एल.डी. कैपेसिटी क सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण।	9 75	डी.पी.आर.विरचन का कार्य मार्च माह तक पू कर लिया जायेगा।
	WSS01 HLD	हल्द्वानी में 15 ओवर हेड टैंक का निर्माण ए उनकी राईजिंग मेन का बिछाया जाना।	2 45	डी.एस.सी.द्वारा मास्टर प्लान तथा डी.पी.आ पी.आई.यू. को जमा कराया जा चुका है जिस प आख्या वांछित है।
	WWM 1HLD	हल्द्वानी में 10 एम.एल.डी. कैपेसिटी क सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण।	50 00	डी.एस.सी.द्वारा कॉन्सेप्ट रिपोर्ट तथा डी.पी.आ पी.आई.यू. को जमा कराया जा चुका है जिस प

				आख्या वांछित है।
	WSS01 RN	रामनगर शहर के वाटर सप्लाई का बढ़ाय जाना एवं पुनर्गठन।	5 00	डी.एस.सी.द्वारा मास्टर प्लान जमा कराया ज चुका है जिस पर आख्या वांछित है।
	WWM 1RN	रामनगर शहर के सीवरेज सिस्टम क नवीनीकरण।	2 00	डी.एस.सी.द्वारा मास्टर प्लान जमा कराया ज चुका है जिस पर आख्या वांछित है।
	WWM 2RMR	रामनगर में 15 एम.एल.डी. कैपेसिटी क सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण।	1 00	डी.एस.सी.द्वारा मास्टर प्लान जमा कराया ज चुका है जिस पर आख्या वांछित है।
	WSS01 PT	पिथौरागढ़ शहर के वाटर सप्लाई का बढ़ाय जाना एवं पुनर्गठन।	5 00	डी.एस.सी.द्वारा मास्टर प्लान जमा कराया ज चुका है जिस पर आख्या वांछित है।
	WWM 1PT	पिथौरागढ़ शहर ट्रंक एवं सीवरेज लाईन क बिछाया जाना।	4 00	डी.पी.आर. जमा कर दी गयी है।
	WWM PT	पिथौरागढ़ शहर में 2 नग सीवेज ट्रीटमेन प्लान्ट का निर्माण।	1 00	डी.एस.सी.द्वारा कॉन्सेप्ट रिपोर्ट पी.आई.यू. क जमा कराया जा चुका है जिस पर आख्य वांछित है।
कार्यों की कुल लागत			त ग ग 98 00	

शहरी विकास विभाग

उत्तराखंड शासन

ऑउटकम बजट

वित्तीय (वर्ष 2011–12)

बिन्दु संख्याः– 1 विभाग के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरणः–

संगठनात्मक ढांचा

1–शहरी विकास विभाग द्वारा नगर स्थानीय निकायों के साथ–साथ राज्य नगर अभिकरण द्वारा संचालित नगरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन किया जाता है।

2–शहरी विकास द्वारा निर्धारित नीतियों, निर्देशों का स्थानीय निकायों से अनुपालन सुनिश्चित कराना, समय–समय पर उनक अनुश्रवण करना। इसके अतिरिक्त नागर स्थानीय निकायों के केन्द्रियत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव तथा सेवा नियमावली के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी शासन द्वारा प्रतिनिधायनिता अधिकारों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करना, स्थानीय निकायों को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग नगरीय अवस्थापना निधि आदि के लिये आवंटित अनुदानों के उपभोग पर भी नियन्त्रण करना। नागर निकायों के लिये प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत अधिनियमों/नियमों एवं उप नियमों का सम्यक् अनुश्रवण का कार्य भी किया जाता है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें

(A)जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन की शुरूआत की गयी। मिशन की अवधि वर्ष 2005–06 से आरम्भ होकर 07 वर्ष की है। इस अवधि के दौरान शहरों का सुस्थिर विकास सुनिश्चत होगा। इस मिशन की चार मुख्य घटक हैः–

1. मिशन शहरों के लिये शहरी अवस्थापना विकास योजना (U.I.G)।

2. मिशन शहरों के लिये बेसिक सर्विसेज अर्बन पुअर (BSUP)

3. नॉन मिशन शहरों के लिये छोटे एवं मझौले शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (UIDSSMT)

4. नॉन मिशन शहरों के लिये इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डवलपमेन्ट प्रोग्राम (IHSDP)

अवस्थापना विकासः– भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड़ राज्य के चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, में तीव्रगामि नियोजित विकास को प्रोत्साहित करना है। जिसमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में दक्षता तथा सेवा आपूर्ति जैसेः– जलापूर्ति, मलवेयन, और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण, पुरात्तत्व क्षेत्रों आदि के विकास पर केन्द्रीभूत ध्यान देना।

योजना के अन्तर्गत सृजित परिसपत्ति और परिसम्पत्ति प्रबन्ध के बीच प्रभावी सामन्जस्य स्थापित करना ताकि नगरों में सृजित अवसंरचना सेवाओं के सही ढ़ग से रखरखाव के अलावा ये सेवाएं समय के साथ–साथ स्वपोशित भी बन सकें।

बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर :– भारत सरकार द्वारा संचालित इस परियोजना के अन्तर्गत चयनित मिशन शहरों में उन स्लम वासियों, जिनके पास आश्रय नही है तथा जीर्ण–शीर्ण दशाओं में रहते है कि दशाओं में सुधार करने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाते हए लाभ इस परियोजना के अन्तर्गत मिलेगा।

इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड़ राज्य के चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, में स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसेः–बेहतर आवास/समेकित विकास,/जलआपूर्ति– सफाईव्यवस्था, सहित, बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं उपलब्ध करते हुए स्वास्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण वाले स्लमविहीन शहरों के लिये प्रयास करना है।

यूआईडीएसएसएमटी :– भारत सरकार द्वारा संचालित यह योजना उत्तराखण्ड़ राज्य के चयनित तीन मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, को छोडकर राज्य के अन्य सभी शहरों/कस्बों के लिये लागू है। इसके द्वारा इन नगरों में तीव्रगामि नियोजित विकास को प्रोत्साहित करना है। जिसमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में दक्षता तथा सेवा आपूर्ति जैसेः– जलापूर्ति, मलवेयन, और ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन, सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण, पुरात्तत्व क्षेत्रों का आदि के विकास पर केन्द्रीभूत ध्यान देना ।

योजना के अन्तर्गत सृजित परिसपत्ति और परिसपत्ति प्रबन्ध के बीच प्रभावी सांमजस्य स्थापित करना ताकि शहरी गरीबी हेतु नगरों में सृजित अवसंरचना सेवाओं के सही ढ़ग से रखरखाव के अलावाये सेवाएं समय के साथ–साथ स्वपोशित भी बन सकें।

इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डवलपमेन्ट प्रोग्राम :– भारत सरकार द्वार संचालित यह परियोजना राज्य के चयनित मिशन शहरों को छोडकर राज्य में अन्य सभी शहरों/कस्बों के लिये लागू है। इस परियोजना के अन्तर्गत उन स्लम वासियों, जिनके पास आश्रय नही है तथा जीर्ण–शीर्ण दशाओं में रहते है कि दशाओं में सुधार करने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाते हुए, इस परियोजना के अन्तर्गत लाभ मिलेगा।

इस परियोजना के अन्तर्गत चयनित शहरों में स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसेः–बेहतर आवास/समेकित विकास/जलआपूर्ति–सफाईव्यवस्था, सहित बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं उपलब्ध करते हुए स्वास्थ्य एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण वाले स्लविहीन शहरों के लिये प्रयास करना है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

यह एक केन्द्र पुरोधानित योजना है, जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश का अनुपात 90:10 है। संशोधित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के दिशा–निर्देश दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है।

उद्देश्य

संशोधित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैः–

- शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार गरीबों को उनके भरण–पोषण के लिए सहायता मुहैया कराकर स्व–रोजगार उद्यम (व्यक्तिगत् या समूह) स्थापित करना अथवा मजदूरी रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करके लाभप्रद रोजगार के माध्यम से शहरी गरीबी उपशमन करना।
- कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता करना ताकि शहरी गरीब, बाजार द्वारा दिए गए रोजगार अवसर प्राप्त कर सकें अथवा स्व–रोजगार शुरू कर सकें।

घटक

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैः–

शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम (ऋण और सब्सिडी):–स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के इस घटक में लाभप्रद स्व–रोजगार लघु उद्यम स्थापित करने हेतु व्यक्तिगत् शहरी गरीब लाभार्थियों को सहायता मुहैया कराने पर बल दिया गया है।

लक्ष्य समूहः–शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम (ऋण और सब्सिडी) में योजना आयोग द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट गरीबी रेखा से नीचे की शहरी आबादी को लक्ष्य बनाया जायेगा।

यूएसईपी के अन्तर्गत वित्तपोषण पद्धति के ब्यौरे इस प्रकार हैः–
अधिकतम अनुमेय यूनिट परियोजना लागत– 200,000/–रू0
अधिकतम अनुमेय सब्सिडी – परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, जो अधिकतम 50,000/–रू0
लाभार्थी अंशदान– परियोजना लागत का 5 प्रतिशत मार्जिन राशि के रूप में कोई समर्थन अपेक्षित नहीं।
माह मई 2010 तक रू0 1.95 लाख धनराशि व्यय कर 9 लाभार्थियो को लाभान्वित किया गया।

शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (यूडब्लूयूएसपी) :– यह परियोजना शहरी गरीब महिलाओं को विशेष प्रोत्साहान देने हेतु प्रतिष्ठित है, जो व्यक्तिगत प्रयास के विपरीत, समूह में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने का निर्णय लेती है। इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिये, यूडब्लूयूएसपी समूह में न्यूनतम 5 शहरी गरीब महिला शामिल होनी चाहिए। समूह उद्यम स्थापित करने के लिये यूडब्लूयूएसपी दल रु0 3.00 लाख या परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या 60,000 हजार की धनराशि दल के प्रति सदस्य के आधार पर, इनमें से जो भी न्यूनतम हो तो उस राशि के सब्सिडी के पात्र होगा। समूह को मार्जिन राशि के रुप में परियोजना लागत का 5 प्रतिषत अंशदान नगद करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

शहरी महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि):–शहरी महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि) के अन्तर्गत महिलाओं द्वारा एक स्वयं सहायता दल/थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाईटी के रूप में गठन किया जाता है तो उक्त समूह को कम से कम एक वर्ष कार्य करने के उपरान्त रू0 2000/– अधिकतम प्रति सदस्य की दर से रू0 25000/– की एक मुश्त अनुदान राशि आवर्ती निधि में प्राप्त करने का अधिकार होगा।

शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण (एसटीईपी–यूपी) (स्अेप–अप):–स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के इस घटक में शहरी गरीबों के कौशल निर्माण/उन्नयन हेतु सहायता मुहैया कराने पर जोर दिया जाएगा ताकि वे स्वः रोजगार चलाने के साथ–साथ बेहतर वेतनभोगी रोजगार प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा सकें।

प्रशिक्षण हेतु औसत इकाई लागत 10,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी से अधिक नही होगी, जिसमें मैटिरियल लागत, प्रशिक्षण शुल्क, टूल किट लागत, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वहन किए जाने वाले अन्य विविध खर्चे और प्रशिक्षणार्थी को दिया जाने वाला मासिक वजीफा शामिल है।

शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्लूईपी):– इस कार्यक्रम में शहरी निकायों के अधिकार क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लाभार्थियों द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पतियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का प्रयोग करके उन्हें मजदूरी रोजगार मुहैया करवाने की अपेक्षा की गई है। ये परिसम्पत्तियां सामुदायिक अवसंरचना द्वारा निर्धारित कम्यूनिटि सेन्टर, वर्षा जल विकास, सड़कें, रात्री निवास, मिड–डेमील स्कीम के तहत प्राथमिक पाठशालाओं में किचन शेड और अन्य सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे पार्क, ठोस कचरा प्रबन्धन व्यवस्था के रूप में हो सकती है।

एकीकृत कम लागत व्यक्तिगत षौचालय

उद्देश्यः–

स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्थिति के अनुरूप समुचित परिवर्तन करके (क्षेत्र विशिष्ट शौचालय) तथा अधिसंरचनाओं सहित दो गड्ढे वाले जल वाही शौचालयों का निर्माण करके और जहां ईडब्यूएस परिवारों के पास में कोई शौचालयों नही है व खुले में मल त्याग की प्रथा मौजूद है, वहां नए शौचालयों का निर्माण करके कम लागत की सफाई यूनिटों का निर्माण/परिवर्तन करना है। इससे कस्बे में समग्र सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा।

स्कीम में वित्तपोषण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :–

केन्द्रीय सब्सिडी 75:, राज्य सब्सिडी 15: और लाभार्थी अंश 10:। लागत की अधिकतम ऊपरी सीमा भी अधिसंरचना सहित एक गर्त जलवाली व्यैक्तिक शौचालय की एक इकाई के लिए 10,000 रूपए होगी। (राज्यों के दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर) दुर्गम/पहाड़ी वर्ग में आने वाले राज्यों के लिए, प्रत्येक गर्त शुद्ध जल वाही शौचालयों के लिए 25: अतिरिक्त लागत की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना

योजनान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जन शौचालयों, स्नानगृह एवं अन्य स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थापना, ड्रैनेज व्यवस्था, वर्षा जल दोहन, आपदा प्रबन्धन/निराकरण सम्बन्धी अवस्थापना, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाए स्वीकृत की जाएगी।

अनुदान सीमा

स्वीकृत परियोजना के लिए निकाय का अंश 30 प्रतिशत तथा राज्यांश 70 प्रतिशत होगा।

मुख्यमंत्रीं निर्मल नगर पुरूस्कार योजना

योजना के अन्तर्गत उन नगर निकायों को प्रतिवर्ष पुरूस्कृत किया जाएगा, जिनके द्वारा कूढा एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, जैविक अपशिष्ट का उपचार, अजैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्रीकरण एवं पुर्नउपयोग तथा शेष बचे अपशिष्ट का वैज्ञानिक भू–भरण सुनिश्चित करने के साथ–साथ स्वच्छता नीति में प्रावधानित हस्तक्षेपों द्वारा पूरे नगरीय क्षेत्र को खुला शौचमुक्त करने और समस्त शौचालयों को सुरक्षित प्रकृति के बनाने में सराहनीय कार्य किया जायेगा।

पुरूस्कार राशि

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाली नगर निगम/नगर पालिका परिषद को क्रमशः रू0 50.00 लाख, 25.00 लाख तथा 10.00 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाली नगर पंचायत को क्रमशः रू0 25.00 लाख, 20.00 लाख तथा 10.00 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा।

प0 दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग एवं वायबिलिटी गैप योजना

योजनान्तर्गत निकाय की आय में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत पीपीपी मोड/वायबिलिटी गैप फण्डिंग के तहत पार्किंग, शापिंग काम्पलेक्स, पार्को का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, स्लाटर हाउस, सामुदायिक भवन/ऑडिटोरियम, टाउन हाल के साथ–साथ ऐसी परियोजनायें जो स्थानीय भौगोलिक एवं जनसुविधाओ के दृष्टिगत अत्यन्त आवश्यकीय हो को वित्त पोषित किया जाएगा।

अनुदान सीमा

परियोजनायें, पी0पी0पी0/बी0ओ0टी0 सिद्वान्त पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, पी.पी.पी. नीति एवं उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना, 2008 के प्रावधानों के अर्न्तगत बनाई जायेंगी।

चयन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना एवं प0 दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग एवं वायबिलिटी गैप योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायो के बोर्ड से अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों के चयन हेतु निम्न पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है :–

निदेशक, शहरी विकास की अध्यक्षता में गठित 'स्क्रीनिंग कमेटी' द्वारा उपयुक्त परियोजना प्रस्तावों का चयन कर उसे संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा।

शासन स्तर पर गठित टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षण कर उपयुक्त प्रस्तावों को विभागीय समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

बिन्दु संख्या :–2

विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना (वर्ष 2011–12) के सम्बन्ध में सूचना

धनराशि लाख रू0

	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	बजट		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट
				प्लान			

	2217–3–191–01–010–20 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (केन्द्र सहायति)	यह ए केन्द्र पुरोधानित योजना जिसमें केन्द्रां और राज्यां का अनुपा 90:10 है संशोधित स्व जयन्ती शह रोजगार योजना दिशा–निर्देश दिनांक अप्रैल, 200 से प्रभावी है उद्देश्य संशोधि स्वर्ण जयन्त शहरी रोजग योजना उद्देश्य इ प्रकार है: • शह बेरोजगारों अथवा अत रोजगार गरी को उन भरण–पोषण के लि सहायता मुहै कराकर		86.05	इस योजना के माध्यम 792 शहरी बेरोजगारो व अपना निजी व्यवसा स्थापित करने, 2100 लो को कौशल सुधार माध्यम से प्रशिक्षित करना		इसके माध्यम शहरी बेरोजगारो अपना निजी व्यव स्थापित करना, कौ सुधार के माध्यम प्रशिक्षण प्रदान व स्वावलम्बी बनान

			स्व–रोजगार उद्यम (व्यक्तिगत् स समूह) स्थापि करना अथ मजदूरी रोजगार शु करने के लि उन्हें प्रोत्साहि करके लाभप्र रोजगार माध्यम शहरी गरी उपशमन करना। • कौश विकास औ प्रशिक्षण कार्यक्रमों लिए सहायत करना ता शहरी गरी बाजार द्वा दिए ग रोजगार अवसर प्रा कर स अथवा स्व–रोजगार शुरू कर सके				

	2217—3—800—01—010—20 कम लागत व व्यक्तिगत शौचालय (केन्द्र सहायति)	स्कीम व उद्देश्य शहर क्षेत्रों स्थानीय स्थिति के अनुरूप समुचित परिवर्तन करन (क्षेत्र विशिष्ट शौचालय) तथ अधिसंरचनाओं सहित व गड्ढे वाल जल वाह शौचालयों व निर्माण करन और जह ईडब्यूएस परिवारों व पास में को शौचालयों नह है व खुले मल त्याग व प्रथा मौजूद है वहां न शौचालयों व निर्माण करन कम लागत व सफाई यूनिट का निर्माण/परिव र्तन करना है इससे कस्बे समग्र सफा व्यवस्था सुधार आएगा	10.00	1613 शुष्क शौचालयों क जल प्रवाहित में परिवर्तित करना।		कम लागत की द्वारा शुष्क शौच को जल प्रवाहित परिवर्तित एंव शौच विहीन आवासों में प्रवाहित शौचालयों निर्माण स्वच्छतापूर्ण उ आधार उपलब्ध कर

	2217–3–800–01–010–20 राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (NURM) (केन्द्र सहायति)	भारत सरक द्वारा संचालि इस योजना अन्तर्गत उत्तराखण्ड़ राज्य चयनित ती मिशन शह देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, तीव्रगामि नियोजित विकास प्रोत्साहित करना जिसमें शह इंफ्रास्ट्रक्चर दक्षता त सेवा आपू जैसेः– जलापूर्ति, मलवेयन, औ ठोस अपशि प्रबन्धन, सड़कों निर्माण सुदृढ़ीकरण, पुरात्तत्व क्षे आदि विकास केन्द्रीभूत ध्या देना।		7500 00	इस परियोजना के द्वा नगरीय क्षेत्रों में जलापू सफाई, सीवरेज, ठो कचरा प्रबन्धन, रो नेटवर्क, शहरी परिवहन सुधार व विकास करना देहरदून में 30 नलकू (टूवैल) 44 जलाश (ओवर है 30 टैन्क/सीडब्लूआर) निर्माण तथा 16 चौराहो चोड़ीकरण, हरिद्वार में 2 नलकूपों (टूवैल) 0 जलाशयों (ओवर हैड टैन्क तथा 12 चौराहो निर्माण, नैनीताल 0 Infiltration Well का निर्माण 03 नलकू (टूवैल) 02 उथ (Shallow) नलकू 01 गहरे (Deep) निर्माण इसके अतिरि देहरादून, हरिद्वार नैनीता सीवरेज सिस्टम का सुध किया जायेगां		इस परियोजना देहरादून, हरिद्वार नैनीताल में निवासरत् लोगो सुचारू पानी व्यवस्था तथा सी तथा ठोस अप प्रबन्धन का मिलेगा साथ यातायता के सु संचालन हेतु स का विकास होगा।

	2217–3–191–01–010–20 आवास एवं मलिन बस्ती सुधार (IHSDP)(केन्द्र सहायति)	भारत सरक द्वार संचालि यह परियोजन राज्य चयनित मिश शहरों व छोडकर राज्य के अन्य स शहरों/कस्बों के लिये ला है। इ परियोजना अन्तर्गत उ स्लम वासिय जिनके पा आश्रय नही तथा जीर्ण–शीर्ण दशाओं रहते है दशाओं सुधार करने लिये ए दृश्टिकोण अपनाते ह इस परियोजन के अन्तर्ग लाभ मिलेगा।		6795 97	5032 भवनों का निर्मा कार्य किया जाना त स्लम विहीन नगरो व विकास किया जायेगा जिससे शहरी गरीबों लिये किफायती कीमतों टेन्योर की सूरक्षा, बेहत आवास, जलापूर्ति, सफा सुविधा सहित बुनिया सेवाओ का प्रावधान औ शिक्षा, स्वास्थ्य त सामाजिक सुरक्षा व फायदा होगा।		19 नगर निका शहरी गरीबों के किफायती कीमतो टेन्योर की सू बेहतर आ जलापूर्ति, स सुविधा सहित बुनि सेवाओ का प्रा और शिक्षा, स्व तथा सामाजिक उपलब्ध क जायेगी।

	2217–3–800–01–010–42 नगरीय अवस्थाप ना सुविधाअ का सुदृढ़ीकरण UIDSSMT 60 प्रतिशत केन्द्र सहायति)	भारत सरका द्वारा संचालि यह योजन उत्तराखण्ड़ राज्य चयनित ती मिशन शह देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, व छोडकर राज के अन्य स शहरों/कस्बों के लिये ला है। इसके द्वा इन नगरों तीव्रगमि नियोजित विकास व प्रोत्साहित करना जिसमें शह इंफ्रास्ट्रक्चर दक्षता तथ सेवा आपू जैसेः– जलापूर्ति, मलवेयन, औ ठोस अवशिष प्रबन्धन, सड़कों व निर्माण सुदृढ़ीकरण, पुरात्तत्व क्षे का आदि	100.00	मसूरी नगर में सीवरेज सिस्टम व एस0टी0पी0 क निर्माण		

		विकास प केन्द्रीभूत ध्या देना ।					
	2217– 3–800– 01–010 –20 बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर (BSUP (NUR M के अन्तर्गत केन्द्र सहायति)	परियोजना अन्तर्गत उत्तराखण्ड़ राज्य चयनित ती मिशन शह देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, स्लमवासियों को समुचि आश्रय त बुनियादी अवस्थपना सुविधाएं जैसेः–बेहतर आवास / समे कत विकास, / जल आपूर्ति– सफाईसुविधा, सहित बुनियादी अवस्थापना		1230 00	1799 भवनों का निर्मा कार्य किया जाना त स्लम विहीन नगरो व विकास किया जायेगा जिससे शहरी गरीबों लिये किफायती कीमतों टेन्योर की सूरक्षा, बेहत आवास, जलापूर्ति, सफा सुविधा सहित बुनिया सेवाओ का प्रावधान औ शिक्षा, स्वास्थ्य त सामाजिक सुरक्षा व फायदा होगा।		तीन मिशन श देहरादून, हरिद्वार के शहरी गरीबों किफायती कीमतों सूरक्षा, बेहतर जलापूर्ति, सफाई बुनियादी सेवाओ और शिक्षा, स्व सामाजिक सुरक्ष करायी जायेगी।

		सुविधाओं उपलब्ध कर हुए स्वास्थ एवं अनुकू शहरी पर्यावर वाले स्लविही शहरों के लि प्रयास कर है।					
	2217–3–191–03–030–42 मौहल्ला स्वच्छत समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन	निकायों सृजित मौहल्ला स्वच्छता समिति व मानदेय भुगतान ए सफाई उपकरण क्रय हेतु दि जायेगा।		43.00	मौहल्ला स्वच्छता समि को भुगतान किया जाये एवं उपकरण क्रय जायेगा		मौहल्ला स्व समिति द्वारा घर से कूड़ा एकत्रित उन्हें निश्चित तक पहुँचाया ज जिससे शहर में कम होगा।
	2217–3–191–03–030–20 **(UA-URIF उत्तरांच ल शहर स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साह निधि**	योजना अन्तर्गत उ न्नगर निका को प्रोत्साहनस्वरू प्रतिवर्श पुरूस्कृत कि जाएगा, जिन द्वारा कू एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, जैविक अपशिष्ट व		118.50	इसके अन्तर्गत उन नग निकायों को प्रोत्साह स्वरूप पुरूस्कार वितरि किया जायेगा।		इससे निकाय क्षे कूड़े कचरे का उ प्रबन्धन होगा। जै व अजैविक अप का उचित उपचा पुर्नचक्रीकरण करते पुर्नउपयोग जोयगा तथा वैज्ञा एंव सुरक्षित विधि निस्तारित जायेगा।

		उपचार, अजैविक अपशिष्ट व पुनर्चक्रीकरण एवं पुर्नउपयो तथा शेष ब अपशिष्ट व वैज्ञानिक भू–भरण कर निकाय क्षे को स्वच रखने व प्रयास करेगें।					
	2217–3–191–03–030–20 नगरीय अवस्थाप ना सुविधाअ का विकास	प्रश्नगत् धनराशि व उपयोग म मुख्यमंत्री समेकित अवस्थापना विकास योजन के अन्तर्ग स्वीकृत परियोजनाओं के लिये कि तथा नगरी निकायो अवस्थापना विकास योजन के अन्तर्ग धनराशि अवमुक्त व जायेगी।		668.0 0	स्थानीय निकायो ड्रेनेज, वर्षा जलदोहन, ठो अपशिष्ठ प्रबन्धन व व्यवस्था तथा अन अवस्थापकीय सुविधाओ व विकास किया जायेगा।		शहरों के विकास लिए केन्द्र सहाय एंव वाह्य सहाय योजनाओं के संच के बाचजूद विकास कई ऐसे क्षेत्र हैं, इन योजनाओं से न आच्छादित हो पा है और न ही राज्य सभी नगरों को योजनाओ का लाभ

	2217–91–97–9701–1 **(बाह्य सहायति) नगरीय अवस्थाप ना का सुदृढ़ीक ण व्यावसारि क तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान**	ADB सहयोग से 3 शहरो नगरीय अवस्थाना जै सीवरेज, वॉट सप्लाई तथ स्लम व सुदृढ़ीकरण विकास किय जायेगा।		10000 .00	इस परियोजना अन्तर्गत चिह्नित 31 नगा में सड़क, सीवरेज व ड्रेने का निर्माण किया जायेगा।		नगरो में आव अवस्थापना सुवि का विकास होगा।
	2217–01–08–42 व 1 परियोजन ाओं की प्रारंभिक तैयारिय एवं रिपोर्ट तैयार करने हे	जे0एन0एन0 0आर0एम0 योजनान्तर्गत DPR तैय करने ए रि–फॉर्म व लागू कि जाने हे विषेशज्ञों व सेवायें प्राप करने हे किया जायेगा		39.50	विभिन्न योजनाओ अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैय करना।		विभिन्न विका योजनाओ के अन्त डी0पी0आर0 तैय करना।
	2217–3–088–04–22 कंप्युटरा जेशन	राज्य व निकायों कप्युटराईजेश एण्ड जी.आ एस. सेवा		25.00	इससे वास्तवि सम्पत्तियो का निर्धार किया जा सकेगा।		सम्पत्तियो चिह्नीकरण होगा तद्नुसार पालिकाये अधिर कर सकती है। जि

	एण्ड जी आई.एस						आय का सजृन साथ ही नगर अन्दर होने आवश्यक वि कार्यो के योजनाये तैयार की रही है।
	राजीव आवास योजना	31 शहरो नगरीय अवस्थाना जै सीवरेज, वॉट सप्लाई तथ स्लम व सुदृढ़ीकरण विकास किय जायेगा।		100.0 0	63 नगर निकायो स्लमों के सर्वेक्षण का का कराया जाना है।		63 नगर निकाय स्लमों के सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने राज्य सरकार टेन्योर राईट उप कराने के बाद अ हीन गरीबो के आवासो का नि किया जायेगा।
	2217—0 3—191—03—030 —20 व 42 नगरीय क्षेत्रों में सार्वभौम रोजगार योजना	राज्य सरका द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अन्तर्गत शहरी बेरोजगार पात्र लाभार्थियो को स्वःरोजगार स्थापित करने हेतु बैंको व माध्यम से सहायता प्रदा की जाती है। जिसमें अधिकतम रू0 15000 का		4.85	1062 लोगो व स्वःरोजगार स्थापित कर का लक्ष्या रखा गया है।		इसके माध्यम शहरी बेरोजगारो अपना निजी व्यवस स्थापित कर स्वाव बनाना।

		अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।					

बिन्दु संख्याः– 3 विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल (**Initiatives**)

1–निकायों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना।

स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिये उनके द्वारा अधीरोपित करों के निर्धारण एवं उनकी वसूली प्रक्रिया में व्यापक सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगर निकाय अधिकतम राजस्व वसूली कर सकें, जिसकें अन्तर्गत जी0आई0एस0 या अन्य अति आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग करते हुए भवन कर को वसूल किये जाने की प्रणाली विकसित करने की योजना है।

2–Aराज्यों के सभी शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा सिटी सैनिटेशन योजना के माध्यम से पूर्ण रूप से स्वच्छ तथा खुला शौच मुक्त बनाना।

सम्पूर्ण राज्य की नगर निकायों में कूड़े कचरे के उचित प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (प्रबन्धन एंव हथालन) नियम, 2000 तथा राष्ट्रीय स्वच्छता नीति, 2008 के अनुरूप सिटी सैनिटेशन प्लान बनाये जाने तथा उसके क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय निकायों द्वारा कार्य किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार 4–5 शहरों के कलस्टर में कचरें के प्रबन्धन/सैनिटरी लैंडफिल की व्यवस्था जिलाधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

2–Bसभी नगरों की सीवरेज तथा ड्रेनेज की समस्या के निदान हेतु मास्टर प्लान तैयार कर क्रियान्वित किया जाना।

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्र पोषित/एडीबी सहायतित परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न नगरों में जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज आदि कार्य कराये जायेगें। अवशेष गैप्स की पूर्ति पेयजल विभाग, जो कि इन योजनाओं हेतु उत्तरदायी विभाग है, की केन्द्र पोषित/राज्य सैक्टर एवं वित्त आयोग की योजनाओं से किया जायेगा।

3–राज्य के शहरों को मलिन बस्ती मुक्त बनाना।

राज्य में घोषित तथा अघोषित 571 मलिन बस्तियों में कुल जनसंख्या लगभग 7 लाख है। जिनके लिये लगभाग 1.40 लाख पक्के आवासो की आवश्यकता है। वर्तमान में केन्द्र पोषित योजनायें बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी योजनाओं के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में 10 परियोजनायें संचालित है तथा 23 नवीन परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। उक्त समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 6738 आवासों का निर्माण किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा देहरादून नगर का चयन राजीव आवास योजना के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें 02 लाख की जनसंख्या हेतु लगभग 29,000 आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

4–निकायों में अवस्थापना विकास कार्य हेतु वित्तीय साधन जुटाना। अवस्थापना विकास कार्यो में पी0पी0पी0 मोड़ को विशेष प्राथमिकता देना।
अवस्थापना विकास कार्यो हेतु संसाधनों की कमी को दृष्टिगत् रखते हुए पी0पी0पी0 मोड़ में उक्त कार्यो को करने पर विशेष जोर दिया जायेगा।
5–स्ट्रीट लाईट विद्युत बिलों के वित्तीय भार से निकायों को मुक्त कराया जाना
द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार सभी विद्युत बिलों में सरचार्ज/सेस लगवाकर स्थानीय निकायों को स्ट्रीट लाईट बिलों के भार से मुक्त किया जाना।

6–स्थानीय निकायों का गठन/वर्गोत्थान।

राज्य की सभी निकायों में वर्गोत्थान के लिये शासन द्वारा मानक निर्धारित कर दिये गये है। निकायों को मानकों के आधार पर निगमों/नगर पालिका परिषद् श्रेणी–1, श्रेणी–2, श्रेणी–3, श्रेणी–4 तथा नगर पंचायत में वर्गोत्थानित किया जायेगा। जो ग्राम नगर के रूप में विकसित हो गये है उन्हें नगर पंचायत का दर्जा दिया जायेगा।

7–74वें संविधान संशोधन के अनुसार निकायों को व्यापक अधिकार प्रदान कर स्वायत्तशासी बनाना।
उत्तराखण्ड स्थानीय निकाय अधिनियम का प्रस्तावित ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जिसमें 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप निकायों के व्यापक अधिकार दिये जाने तथा तद्नुसार व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान भी है। भारत सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत अपेक्षित सुधारों, जिसमें 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत व्यापक अधिकारी भी सम्मिलित है, को सभी निकायों में लागू कराया जाना।

8–नगर निकायों में सुधार आधारित मुख्यमंत्री समेकित विकास योजना लागू कर नगरों में सभी आधारभूत पर्याप्त नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराना।
1–मुख्यमंत्री समेकित शहरी अवस्थापना विकास योजना के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जन शौचालयों, स्नानगृह एवं अन्य स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थापना, ड्रैनेज, वर्षा जल दोहन एवं आपदा प्रबन्धन/निराकरण सम्बन्धी अवस्थापकीय कार्य कराये जाना।
2–पं0 दीनदयाल उपाध्याय शहरी वायबिलिटी गैप योजना के अन्तर्गत आयपरक गतिविधियों तथा–कार पार्किंग, शॉपिग कॉम्पलैक्स, पार्को का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, स्लास्टर हाउस, सामुदायिक भवन/आडिटोरियम तथा अन्य ऐसी योजनायें जो स्थानीय भौगोलिक एवं जनसुविधाओ के दृष्टिगत आवश्यक हो, ली जायेगी। पीपीपी के अन्तर्गत निकायों के आय सृजन को भी दृष्टिगत् रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पीपीपी सेल के सहयोग से वाएबिलिटी गैप फण्डिंग करते हुए सहायता प्रदान की जायेगी, ताकि वर्ष 2020 तक सभी निकायों में उपरोक्तानुसार सुविधायें उपलब्ध हो सकें।
3–शहर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने हेतु प्रोत्साहन स्वरूपम मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरूस्कार योजना प्रारम्भ की गयी है। निकायो को प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक वर्ष न्यूनतम निर्धारित स्वच्छता स्तर प्राप्त करने के प्रतिबन्ध के अधीन सर्वश्रेष्ठ नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रेटिंग प्राप्त करने वाले नगर निकायों को प्रत्येक वर्ष विशेष अनुदान इस योजना के अन्तर्गत दिया जायेगा।

बिन्दु संख्या :–4

योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति के सम्बन्ध में सूचना (वर्ष 2010–11)

धनराशि रू0

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	बजट		आउटपुट		आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धी	आउट	
		प्लान	प्लान		प्लान			

2217—03—191 -01—0101—20 वर्ण जयंती हरी रोजगार योजना (केन्द्र हायतित)	यह एक केन्द्र पुरोधानित योजना है जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश क अनुपात 90:10 है। संशोधित स्व जयन्ती शहरी रोजगार योजना क दिशा—निर्देश दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है उद्देश्य संशोधित स्वर्ण जयन्ती शह रोजगार योजना के उद्देश्य इस प्रक है:— • शहरी बेरोजगारों अथवा अल रोजगार गरीबों को उनके भरण—पोष के लिए सहायता मुहैया कराक स्व—रोजगार उद्यम (व्यक्तिगत् या समूह स्थापित करना अथवा मजदूरी रोजगा शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहि करके लाभप्रद रोजगार के माध्यम से शहरी गरीबी उपशमन करना • कौशल विकास और प्रशिक्ष कार्यक्रमों के लिए सहायता करना ताकि शहरी गरीब बाजार द्वारा दिए ग रोजगार अवसर प्राप्त कर सकें अथव स्व—रोजगार शुरू कर सकें।		67.7		67 77		परि योज ान्तर्ग त 633 स्वः रोज ारला ार्थी संख्य , 1598 प्रशि ण लाभ र्ी स तथा 7740 1 मान दिव सृजि त किये गये।	

2217—03—800 -01—0102—20 कम लागत के यक्तिगत ौचालय (केन्द्र हायतित)	स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों स्थानीय स्थिति के अनुरूप समुचि परिवर्तन करके (क्षेत्र विशिष्ट शौचालय तथा अधिसंरचनाओं सहित दो गड् वाले जल वाही शौचालयों का निर्मा करके और जहां ईडब्यूएस परिवारों पास में कोई शौचालयों नही है व खु में मल त्याग की प्रथा मौजूद है, व नए शौचालयों का निर्माण करके क लागत की सफाई यूनिटों निर्माण/परिवर्तन करना है। इससे कर में समग्र सफाई व्यवस्था में सुधा आएगा।		147.(		0.0 0	79 0 यूनि ट शौच ालय ो का निर्मा ण	
2217—03—800 -01—0105—20 ाष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन NURM) केन्द्र सहायतित	भारत सरकार द्वारा संचालित इ योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड़ राज के चयनित तीन मिशन शह देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, में तीव्रगा नियोजित विकास को प्रोत्साहित कर है जिसमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में दक्ष तथा सेवा आपूर्ति जैसेः— जलापूर्ति मलवेयन, और ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण पुरात्तत्व क्षेत्रों आदि के विकास प केन्द्रीभूत ध्यान देना।		1877 2.1		0.(0	देह रादू न नगर के लिये 17 नल कूप, 17 जला शय 15 पम्प हाउ सो का निर्मा ण कार्य पूर्ण तथा	

						11 चौराहो व देहरादून सीवरेज का कार्य प्रगति पर। हरिद्वार नगर के लिये 17 नल कूप, 8 जलाशय व 6 Infiltration wells का निर्माण कार्य	

						पूर्ण तथा 8 चौराहो का कार्य प्रगति पर नैनीताल नगर के लिये 3 ट्यूब वैल, 2 उथला, 1 गहरे नल कूप का निर्माण कार्य पूर्ण, 2 जल शोधन संय	

						त्रों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित व नैनीताल सीवरेज का निर्माण कार्य पग्रति पर 145 बसे प्राप्त हो गयी है जिन का संचालन उत्तराखण्ड	

						परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा है।	
2217—03—191 -01—0102—20 आवास एवं मलिन बस्ती सुधार IHSDP)(केन्द्र सहायतित)	भारत सरकार द्वार संचालित य परियोजना राज्य के चयनित मिश शहरों को छोडकर राज्य के अन्य सभ शहरों/कस्बों के लिये लागू है। इ परियोजना के अन्तर्गत उन स्ल वासियों, जिनके पास आश्रय नही तथा जीर्ण–शीर्ण दशाओं में रहते है कि दशाओं में सुधार करने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाते हए लाभ इ परियोजना के अन्तर्गत मिलेगा।		607852		1350	521 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 1416 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	

2217—03—800 -01—0104—42 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण UIDSSMT (50 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)	भारत सरकार द्वारा संचालित य योजना उत्तराखण्ड़ राज्य के चयनि तीन मिशन शहरों देहरादून, नैनीताल हरिद्वार, को छोडकर राज्य के अन् सभी शहरों/कस्बों के लिये लागू है इसके द्वारा इन नगरों में तीव्रगति नियोजित विकास को प्रोत्साहित करन है जिसमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में दक्षत तथा सेवा आपूर्ति जैसेः— जलापूर्ति मलवेयन, और ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण पुरात्तत्व क्षेत्रों का आदि के विकास प केन्द्रीभूत ध्यान देना ।		3187 33		0.0 0	1 कि0 मी0 पाई प बिछा ने का कार्य पूर्ण एवं 27 कि0 मी0 पाई प लाई न बिछा ने का कार्य प्रगति पर।	

2217—03—800 -01—0106—20 ासिक सर्विस कॉर अर्बन पुअर BSUP) NURM के अन्तर्गत केन्द्र सहायतित)	परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण राज्य के चयनित तीन मिशन शह देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथ बुनियादी अवस्थपना सुविधा जैसेः—बेहतर आवास/समेकि विकास,/जलआपूर्ति— सफाईसुविध सहित बुनियादी अवस्थापना सुविधाअ उपलब्ध करते हुए स्वास्थ्य एवं अनुकू शहरी पर्यावरण वाले स्लविहीन शहरों लिये प्रयास करना है।		4461 07		90 67	37 भवन ों का निर्मा ण कार्य पूर्ण तथा 137 भवन ों का निर्मा ण कार्य प्रगति पर है।	

2217–03–800–01–0106–20 बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर (BSUP) (NURM के अन्तर्गत केन्द्र सहायतित)	परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण राज्य के चयनित तीन मिशन शह देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, स्लमवासियों को समुचित आश्रय तथ बुनियादी अवस्थपना सुविधा जैसेः–बेहतर आवास/समेकि विकास,/जलआपूर्ति– सफाईसुविध सहित बुनियादी अवस्थापना सुविधाअ उपलब्ध करते हुए स्वास्थ्य एवं अनुकू शहरी पर्यावरण वाले स्लविहीन शहरों लिये प्रयास करना है।		4461 07		90 67			
2217–03–191–03–0302–42 मौहल्ला स्वच्छत समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन	निकायों में सृजित मौहल्ला स्वच्छता समिति को मानदेय के भुगतान एवं सफाई उपकरण के क्रय हेतु दिया जायेगा।		23.0		0. 0			

2217–03–191–03–0303–20 **(UA-URIF) उत्तरांचल शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि**	योजना के अन्तर्गत उन न्रगर निकायों को प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिवर्श पुरूस्कृत किया जाएगा, जिनके द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, जैविक अपशिष्ट का उपचार, अजैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्रीकरण एवं पुर्नउपयोग तथा शेष बचे अपशिष्ट का वैज्ञानिक भू–भरण करके निकाय क्षेत्र को स्वच्छ रखने का प्रयास करेगें।		145.0 0		0.0 0			
2217–03–191–03–0305–20 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	प्रष्नगत् धनराशि का उपयोग मा0 मुख्यमंत्री समेकित अवस्थापना विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिये किया तथा नगरीय निकायो में अवस्थापना विकास योजना के अन्तर्गत धनराषि अवमुक्त की जायेगी।		820.7 5		73 15			
2217–191–97–9701–16 (बाह्य सहायतित) नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	ADB के सहयोग से 31 षहरो में नगरीय अवस्थाना जैसे सीवरेज, वॉटर सप्लाई तथा स्लम का सुदृढ़ीकरण व विकास किया जायेगा।		1150 6.3		30 3.7			
37 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 137 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।			1799 भवनो का निर्माण करते हुए स्लम विहीन नगरो का विकास किया		45 00			

			जायेगा। जिससे शहरी गरीबों के लिये किफायती कीमतों टेन्योर व सूरक्षा, बेहतर आवास, जलापूर्ति, सफाई सुविधा सहित बुनियादी सेवाओ व प्रावधान और शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा व फायदा होगा।					
मौहल्ला स्वच्छता समिति को भुगतान किया जायेगा एवं उपकरण क्रय जायेगा।			नगर निकायो में प्रत्येक घरों से कूड़ा एकत्रित करने		0.00			

			की व्यवस्था से वहाँ के निवासरत लोग लाभान्वित होगें।					
इसके अन्तर्गत उन नगर निकायों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरूस्कार वितरित किया जायेगा।			स्वच्छता के लिये नगर निकायो को पुरूस्कृत कर नगर निकायो में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना। जिस से निकाय के		1700			

			क्षेत्र लाभान्वित होगें।					
नगरीय निकायो में अवस्थापना विकास हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती हैं			नगरीय अवस्थाना में विकास किया जायेगा। जिस से नगरीय क्षेत्रों में खराब नाले व सड़को का विकास होगा। जिस से ड्रेनेज सुविधा सुदृड़ होगी।		0.00			

देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार में सीवरेज पाईप लाईन का निर्माण कार्य किया जा रहा है।			देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार में सीवरेज पाईप लाईन का निर्माण कार्य किया जा रहा है।		0.00			
राजीव आवास योजना की प्रारम्भिक तैयारी प्रारम्भ					0.00			
इस वर्ष इस मद में कोई व्यय नही हुआ।					0.00			
शहरी विकास योजना अुनश्रवण परिषद् के मा0 उपाध्यक्ष के कार्यालय के अनुसांगित का भुगतान किया गया					0.00			

इस वर्ष इस मद में कोई व्यय नही हुआ।					1335			
इस वर्ष इस मद में कोई व्यय नही हुआ।					2500	वेतन आदि के भुगतान के लिये आथि		

						कि सहायता दी गयी।		
विगत् वर्ष समाप्त हुये कुम्भ मेले के लिये स्थापित अधिष्ठान द्वारा किये जा रहे अवशेष कार्यो का अनुश्रवण किया जा रहा है।								

कोई धनराशि अवमुक्त नही की गयी।			वर्ष में दो बार लगने वाले कांवड मेला, सोमवती अमावस्या स्नान पर्व, पूर्णिमा स्नान, शिवरात्रि, बैशाखी, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, चारधाम यात्रा का सुचारू संचालन।					

हरिद्वार कुम्भ 2010 में 140 से अधिक देशों के लोगों द्वारा स्नान किये जाने, वर्ष में दो बार लगने वाले कांवड मेला, सोमवती अमावस्या स्नान पर्व, पूर्णिमा स्नान, शिवरात्रि, बैशाखी, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, चारधाम यात्रा, अर्द्धकुम्भ एवं कुम्भ के दृष्टिगत मंत्रिमण्डल द्वारा मेला प्राधिकरण के गठन पर सैद्वान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए इसके गठन के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही यथाप्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किये								

जाने के निर्देष दिये गये। कुम्भ–2010 मेले में हुए अवस्थापना के कार्यों का संरक्षण, तीर्थों का सौन्दर्यीकरण, हरिद्वार, ऋषिकेश–मुनि कीरेती एवं नीलकठ में होने वाले समस्त मेलों का आयोजन एवं उक्त मेलों हेतु अवस्थापना सुविधायें विकसित करने सम्बन्धी कार्य उक्त मेला प्राधिकरण का गठन किया गया है।								

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित स्थानीय निकायों की सूची

क्र सं०	जनपद का नाम	स्थानीय निकाय का नाम/पता
1	देहरादून	नगर निगम देहरादून
2		नगर पालिका परिषद विकासनगर
3		नगर पालिका परिषद मसूरी
4		नगर पालिका परिषद ऋषिकेश
5		नगर पंचायत हरर्बटपुर
6		नगर पंचायत डोईवाला
7	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद हरिद्वार
8		नगर पालिका परिषद रूडकी
9		नगर पालिका परिषद मंगलौर
10		नगरपचायत झबरेडा
11		नगर पंचायत लक्सर

12		नगर पंचायत लण्ढौरा
13	उत्तरकाशी	नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी
14		नगर पंचायत बडकोट
15		नगर पंचायत गंगोत्री
16	चमोली	नगर पालिका परिषद चमोली–गोपेश्वर
17		नगर पालिका परिषद जोशीमठ
18		नगरपंचायत बद्रीनाथ
19		नगर पंचायत नन्दप्रयाग
20		नगर पंचायत गौचर
21		नगर पंचायत कर्णप्रयाग
22	टिहरी	नगर पालिका परिषद टिहरी
23		नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर
24		नगर पंचायत चम्बा
25		नगर पंचायत किर्तिनगर
26		नगर पंचायत देवप्रयाग
27		नगर पंचायत मुनीकीरेती
28	रूद्रप्रयाग	नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग
29		नगर पंचायत केदारनाथ
30	पौडी	नगर पालिका परिषद पौडी
31		नगर पालिका परिषद श्रीनगर
32		नगर पालिका परिषद दुगड्डा
33		नगर पालिका परिषद कोटद्वार
34	पिथौरागढ	नगर पालिका परिषद पिथौरागढ
35		नगर पंचायत धारचूला
36		नगर पंचायत डीडीहाट
37	चम्पावत	नगर पालिका परिषद टनकपुर
38		नगर पंचायत चम्पावत
39		नगर पंचायत लाहोघाट
40	अल्मोडा	नगर पालिका परिषद अल्मोडा
41		नगर पंचायत द्वाराहाट
42	बागेश्वर	नगर पालिका परिषद बागेश्वर
43	नैनीताल	नगर पालिका परिषद नैनीताल
44		नगर पालिका परिषद रामनगर
45		नगर पालिका परिषद भवाली
46		नगर पालिका परिषद हल्द्वानी
47		नगर पंचायत कालाढुगी
48		नगर पंचायत लालकुंआ
49		नगर पंचायत भीमताल

50	उद्यमसिंह नग	नगर पालिका परिषद गदरपुर
51		नगर पालिका परिषद जसपुर
52		नगर पालिका परिषद काशीपुर
53		नगर पालिका परिषद बाजपुर
54		नगर पालिका परिषद रूद्रपुर
55		नगर पालिका परिषद किच्छा
56		नगर पा0 परिषद सितारगंज
57		नगर पालिका परिषद खटीमा
58		नगर पंचायत महुवाडावरा
59		नगर पंचायत महुआखेडागंज
60		नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी
61		नगर पंचायत केलाखेडा
62		नगर पंचायत दिनेशपुर
63		नगर पंचायत शक्तिगढ

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) में निर्देशित}

मैनुअल – दस	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथा उपबन्धित हो।
मैनुअल – ग्यारह	सभी योजनओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विषिश्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक

	अभिकरण को आवंटित बजट।
मैनुअल – बारह	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि का ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।
मैनुअल – तेरह	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियॉ।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) में निर्देशित}

मैनुअल – दस	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथा उपबन्धित हो।
मैनुअल – ग्यारह	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।
मैनुअल – बारह	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि का ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित है।
मैनुअल – तेरह	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियॉ।

विषय–सूची

क्रम संख्या	विषय
1	प्रस्तावना
	मैनुअल – दस
1.	निदेशालय में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
2.	प्रतिकर प्रणाली
3.	केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
4.	केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रतिकर प्रणाली
	मैनुअल – ग्यारह
1.	शहरी विकास निदेशालय के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत योजनायें
2.	स्वीकृत बजट का विवरण
3.	शहरी विकास निदेशालय से सम्बद्ध अभिकरण अथवा संस्था
4.	शासनादेश संख्या – 2533/रा0वि0आ0/वि0 अनु0–1 दिनांक 26–12–2003
5.	अवस्थापना विकास एवं मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार अवस्थापना विकास हेतु स्वीकृत धनराशि व योजनायें
6.	स्वीकृत योजनाओं व धनराशि की सूची

	मैनुअल – बारह
1.	सहायिकी कार्यक्रम
	मैनुअल – तेरह
1.	रियायतों, अनुज्ञापत्रों की विशिष्टियां

*****

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल–दस

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 (1) (ख) (x) में निर्देशित}

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो विनियमों में यथा उपबन्धित हो।

निदेशालय में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

शहरी विकास निदेशालय के लिए स्वीकृत 44 पदों के सापेक्ष 19 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। इन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक निम्नानुसार हैः –

क्रम सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	मा पारि (मा 20
1.	श्रीमती निधिमणी त्रिपाठी आई0ए0एस0	निदेशक	आई0ए0एस0 संवर्गानुसार	निदे से वे आहर नहीं है
2.	श्री हर्ष वर्धन मिश्रा	उप निदेशक	10000-15200	220 00
3.	श्री सुभाष गुप्ता	उप निदेशक	10000-15200	220 00

4.	श्री बृजमोहन सिंह चौहान	लेखाधिकारी		
5.	श्री पुरूषोत्तम भट्ट	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी		
6.	श्री राकेश मालगुडी	सहायक लेखाकार	5000-8000	11000
7.	श्री विनय नेगी	लेखाकार	5000-8000	
8.	श्री गजेन्द्र सिंह कोरंगा	मुख्य सहायक	4500-7000	11000
9.	कु0 पुष्पा चौधरी	मुख्य सहायक	4500-7000	11000
10.	श्री राजेन्द्र आर्य	मुख्य सहायक	4500-7000	850
11.	श्री कालिका प्रसाद भट्ट	प्रवर सहायक	3050-4590	805
12.	श्री के0 एन0 पाठक	सहायक लेखाकार	4500-7000	863
13.	श्री राम प्रकाश	प्रवर सहायक	4000-6000	724
14.	श्री सुशील डंगवाल	प्रवर सहायक	4000-6000	723
15.	श्री सुनील कुमार	कनिष्ठ सहायक	2550-3200	636
16.	श्री सियाराम	वाहन चालक	3050-4590	656
17.	श्री रमेश काण्डपाल	वाहन चालक	3050-4590	656

18.	श्री चन्द्रपाल	चपरासी	2550-3200	636
19.	श्री रमेश रावत	चपरासी	2550-3200	747

प्रतिकर प्रणाली

निदेशालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों की भांति निम्न प्रतिकर की सुविधायें अनुमन्य हैं: –

(क) पेन्शन

(ख) राशिकरण

(ग) ग्रेच्युटी

(घ) सामूहिक जीवन बीमा

(ड.) निधन अथवा सेवा निवृत होने पर उपार्जित अवकाश नगदीकरण

केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को स्थानीय नगर निकायों की निधि से निकायों द्वारा मासिक वेतन का भुगतान किया जाता है और भुगतान का विवरण स्थानीय नगर निकायों में ही रखा जाता है। निदेषालय स्तर पर इन कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतनमान की ही जानकारी उपलब्ध रहती है जो निम्नानुसार है: –

	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थान	वेतनमान
	एन0के0 पाण्डे	उप नगर अधिकारी	नगर निगम, देहरादून	10000-15200
	हर्षवर्धन मिश्रा	उपनिदेशक	निदेशालय	10000-15200
	सुभाष गुप्ता	उपनिदेशक	निदेशालय	10000-15200
	विचित्र सिंह पंवार	सहायक निदेशक	निदेशालय	8000-13500
	नीरज जोशी	तदैव	न0पा0 नैनीताल	8000-

				13500
	पी0एस0 रावत	तदैव	न0पा0 रुड़की	8000-13500
	मिट्ठन लाल शाह	अधि0 अधिकारी	न0पा0 टिहरी	3200-4900
	भगवती प्रसाद कपरवाण	तदैव	न0पा0जोशीमठ	4500-7250
	रमेश प्रसाद सेमवाल	तदैव	न0पा0प0 श्रीनगर	3200-4900
	बाला दत्त जोशी	तदैव	चम्पावत	3200-4900
	खीमानन्द जोशी	तदैव	न0पा0प0 पिथौरागढ़	3200-4900
	डी0पी0 भट्ट	तदैव	न0पा0प0 ऋषिकेश	3200-4900

	रमेश पन्त	तदैव	न0पा0 अल्मोड़ा	3200-4900
	के0आर0 टम्टा	तदैव	न0प0भीम ताल	3200-4900
	रिक्त	तदैव	न0प0नन्द प्रयाग	3200-4900
	नरेन्द्र कुमार	तदैव	न0पा0 रुद्रपुर	3200-4900
	भजन लाल आर्य	तदैव	नगर निगम देहरादून	3200-4900
	रिक्त	तदैव	नप0चम्बा	3200-4900
	दलीप कपूर	तदैव	गदरपुर	3200-4900
	नजर अली	तदैव	काशीपुर	3200-

				4900
	संजीव मेहरोत्रा	तदैव	महुआखेड़ा गज	3200-4900
	एस0पी0 जोशी	तदैव	न0पा0 विकासनगर	3200-4900
	सुनील अग्रवाल	तदैव	न0पा0 मंगलौर	3200-4900
	दलीप कपूर (अति0)	तदैव	दिनेशपुर	3200-4900
	त्रिलोक पाल आर्य (निल0)	तदैव	न0प0द्वारा हाट	3200-4900
	श्रीमती सरिता राणा	तदैव	न0पं0 डोईवाला	3200-4900
	एल0एम0 दास	तदैव	खटीमा	3200-4900

	बद्रीप्रसाद	तदैव	न0पा0प0 पौड़ी	3200-4900
	शेखर चन्द जोशी	स0परि0 अधिकारी	न0 प0 लोहाघाट	-
	श्रीम0 राजू नबियाल	स0परि0 अधिकारी	लालकुंआ	3050-4590
	शांती प्रसाद भटट	लिपिक	न0पा0प0 गोपेश्वर	4500-7000
	जयवीर राठी	तदैव	न0पा0 किच्छा	3200-4900
	नथुलाल कौली	वर्कएजेन्ट	न0पा0 सितारगंज	3200-4900
	प्रकाश चन्द्र फोनिया	अधि0 अधिकारी	न0पा0उत्तरकाशी	3200-4900

	दिनेश चन्द्र पंत	तदैव	न0पं0 बडकोट	3200-4900
	प्रमोदपुरी	तदैव	न0प0लक्सर	3200-4900
	जीवन्ती जोशी	तदैव	न0प0धारचुला	3050-4590
	रवि पाण्डे	अधि0 अभियन्ता	नगर निगम देहरादून	10000-15200
	आनन्द प्रकाश	सहायक अभि0	मसूरी	4500-7000
	हरीश चन्द जोशी	तदैव	नगर निगम देहरादून	4500-7000
	रविन्द्र सिंह नेगी	तदैव	रामनगर	4500-7000
	जयप्रकाश	तदैव	मसूरी	45

	रतूडी			00-7000
	जगमाल सिंह त्यागी	तदैव	नगर निगम देहरादून	4500-7000
	दिनेश शर्मा	नगर अभियन्ता	नगर निगम देहरादून	4500-7000
	पवन कुमार	तदैव	पौडी	4500-7000
	दिनेश उनियाल	तदैव	नगर निगम देहरादून	4500-7000
	कमल सिंह रावत	तदैव	काशीपुर	4500-7000
	ईश्वरी सिंह	तदैव	नैनीताल	4500-7000
	चन्द्रकांत गुप्ता	तदैव	दुगड्डा	4500-700

				0
	रविन्द्र सिंह पंवार	तदैव	जोशीमठ	4500-7000
	डिगर सिंह मेहरा	तदैव	हल्द्वानी	4500-7000
	हर्षवर्धन सक्सैना	ड्राप्समैन	नगर निगम	4500-7000
	सहेन्द्र सिंह नेगी	तदैव	तदैव	4500-7000
	गुलाब सिंह पंवार	तदैव	विकासनगर	4500-7000
	रमेश बिष्ट	तदैव	टिहरी	4500-7000
	रंजित कुमार	तदैव	ऋषिकेश	4500-7000
	आनन्द	अवर	नरेन्द्र	45

	सिंह मिश्रवाण	अभि0	नगर	00-7000
	वेदप्रकाश बधानी	तदैव	नगर निगम देहरादून	4500-7000
	अनिल नेगी	तदैव	श्रीनगर	4500-7000
	लक्ष्मण सिंह बोहरा	तदैव	टनकपुर	4500-7000
	महेन्द्र सिंह बिष्ट	तदैव	सितारगंज	4500-7000
	उमेश अवस्थी	तदैव	पिथौरागढ	4500-7000
	विनोद थपलियाल	तदैव	रूडकी	4500-7000
	प्रेमकुमार शर्मा	तदैव	रूद्रपुर	4500-700

				0
	राजीव चौहान	अवर अभि0 (स्थानीय व्यवस्था)	गौचर	
	अब्दुल रउफ	वर्कसुपरवाईजर	हरिद्वार	4500-7000
	महेन्द्र कुमार यादव	कर एवं राजस्व निरीक्षक	काशीपुर	3200-4900
	अशोक कुमार गुप्ता	तदैव	हरिद्वार	3200-4900
	लहरी सिंह	तदैव	हरिद्वार	3200-4900
	तेजपाल वर्मा	तदैव	रूडकी	3200-4900

	मनोज कुमार दास	तदैव	हल्द्वानी	3200-4900
	सुनीता सक्सैना	तदैव	रामनगर	3200-4900
	श्यामसुन्दर प्रसाद	तदैव	टिहरी	3200-4900
	अनिल कुमार शर्मा	तदैव	ऋषिकेश	3200-4900
	ईश्वर सिंह	तदैव	नैनीताल	3200-4900
	संजय मेहरोत्रा	मोहर्रिर	काशीपुर	3200-4900
	भुवनचन्द काण्डपाल	मोहर्रिर	रूद्रपुर	3200-4900
	सुरेश चन्द गुप्ता	लेखाकार	ऋषिकेश	4500-

				7000
	ओम प्रकाश आर्य	लेखाकार	नगर निगम	4500-7000
	रमेश चन्द शर्मा	लेखाकार	रूडकी	3200-4900
	अजहर अली	कर एवं राजस्व अधीक्षक	नगर निगम	4500-7250
	दरबान सिंह	तदैव	मसूरी	4500-7250
	उत्तर सिंह नेगी	तदैव	ऋषिकेश	4500-7250
	चन्द्रपाल सिंह	तदैव	हल्द्वानी	4500-7250
	राजेश कुमार	तदैव	नगर निगम	5000-

	नैथानी		देहरादून	8000
	सुशील कुमार कुरील	तदैव	नगर निगम	4500-7250
	संजय कुमार	तदैव	हल्द्वानी	4000-6000
	बचन सिंह जयाडा	जो0से0 अधिकारी	नगर निगम	6500-10500
	आर0के0 अग्रवाल	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	रूड़की	4500-7000
	श्री श्योराज सिंह	स0निरीक्षक	नगर निगम	4500-7000
	बलराम सिंह (पुनर्नियुक्ति)	तदैव	हरिद्वार	4500-7000
	चरण	तदैव	नैनीताल	45

	सिंह			00-7000
	रतन लाल	स0नि0 स्थानीय व्यवस्था	हल्द्वानी	4500-7000
	जगदीश चन्द	स0नि0 स्थानीय व्यवस्था	काशीपुर	4500-7000
	गिरिशचन्दपाण्डे	वैक्सीनेटर	हल्द्वानी	4500-7000
	विरेन्द्र बिष्ट	वैक्सीनेटर	मसूरी	4000-6000
	खुशीराम डोभाल	सफाई नि0	उत्तरकाशी	4500

केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रतिकर प्रणाली

केन्द्रीयत सेवा के अधिकारी व कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के कर्मियों की भांति प्रतिकर की निम्न सुविधायें अनुमन्य हैं: –

(क) पेन्शन

(ख) राशिकरण

(ग) ग्रेच्युटी

(घ) सामूहिक जीवन बीमा

(ड.) निधन अथवा सेवा निवृत होने पर उपार्जित अवकाष नगदीकरण

*****

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) (xi) में निर्देशित}

मैनुअल – ग्यारह

सभी योजनओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्षित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

शहरी विकास निदशलय, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल–ग्यारह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 (1) (ख) (xi) में निर्देशित}

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

शहरी विकास निदेशालय के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत योजनायें

*****

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल–तेरह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 (1) (ख) (xiii) में निर्देशि

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ।

शहरी विकास निदेशालय द्वारा किसी प्रकार की ऐसी योजना या परियोजना संचालित नहीं की जा रही है जिसमें लाभार्थियों को रियायत दी जा रही हो एवं न ही शहरी विकास निदेशालय द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं। कतिपय व्यवसायों के लिए नगर निकायों द्वारा लाइसेंस/अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते है जिसका विवरण सम्बन्धित नगर निकायों के कार्यालय में ही उपलब्ध रहता है।

*****